● वर्ष-5

● अंक-250

रायपुर, शुक्रवार
05 जून 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› मुख्यमंत्री साय ने भिखमपुरा के ...

प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता

तेल संकट से निपटने बड़ी डील

नईदिल्ली। दुनिया की तेल राजनीति में इस समय सबसे गजब का मोर्चा नई दिल्ली में खुलता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए नई धुरी तैयार कर रहा है। पांच दिन के भारत दौरे पर पहुंचीं रोड्रिगेज अपने साथ विदेश, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परिवहन और सूचना मंत्रालयों के वरिष्ठ मंत्रियों का विशाल प्रतिनिधिमंडल लेकर आई हैं। यह यात्रा भारत और वेनेजुएला के बीच उभरते उस रणनीतिक गठबंधन का ऐलान बनी है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, परिवहन, खनिज संपदा और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई। बैठक इतनी अहम रही कि औपचारिक वार्ता कार्यकारी भोज तक चली। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने स्पष्ट कहा कि वेनेजुएला

भारत को ऊर्जा क्षेत्र में अपना पसंदीदा साझेदार मानता है और दोनों देश तेल उत्पादन से लेकर शोधन तक हर स्तर पर सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं।

यह साझेदारी ऐसे समय में मजबूत हो रही है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के टकराव ने वैश्विक तेल आपूर्ति को हिला दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि भारत के चालीस प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत ने वेनेजुएला की ओर कदम बढ़ाया है। मई महीने में भारत ने प्रतिदिन चार लाख सत्ताईस हजार बैरल वेनेजुएलाई तेल खरीदा और वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। यह केवल व्यापारिक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है।

कभी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीद लगभग बंद कर दी थी। लेकिन अब नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा नीति वाशिंगटन की शर्तों पर नहीं चलाएगा। अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने और वेनेजुएला में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत ने कराकस से दूरी बनाने की बजाय संबंध और मजबूत किए हैं। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सबसे सशक्त प्रदर्शन है।

देखा जाये तो भारत के लिए वेनेजुएला केवल तेल का स्रोत नहीं है। वहां सोना, हीरे, निकल, बाक्साइट और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है। वार्ता में खनन सहयोग और संभावित भंडारों के संयुक्त आकलन पर भी चर्चा हुई। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब भविष्य की रक्षा तकनीक, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक उद्योग और विनिर्माण शक्ति के लिए जरूरी संसाधनों पर भी अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है। यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा का एक बेहद दिलचस्प और प्रतीकात्मक पहलू भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद वह आंध्र प्रदेश स्थित सत्य साई बाबा के आश्रम प्रशांति निलयम भी जाएंगी। हम आपको बता दें कि रोड्रिगेज और पूर्व वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लंबे समय से सत्य साई बाबा के अनुयायी रहे हैं। रोड्रिगेज इससे पहले भी दो बार आश्रम का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब भी वह संकट में रहीं, उन्हें साई बाबा का आशीर्वाद अपने परिवार और अपने देश के साथ महसूस हुआ। मादुरो ने भी सत्य साई बाबा को प्रेम, सेवा और सत्य का प्रकाश स्तंभ बताया था।यह तथ्य केवल आध्यात्मिक जुड़ाव की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक प्रभाव भी दिखाता है।

अब विप्रो पर लगा धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप

पुणे/नई दिल्ली। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जबरन इस्तीफा लेने के आरोपों के बीच आईटी कंपनी विप्रो ने कहा कि उसने मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। कंपनी का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है और मामले की जांच जारी है।

आरोपों पर विप्रो ने क्या कहा?

कंपनी ने कहा कि वह जारी जांच में पूरा सहयोग कर रही है और एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटी कंपनी ने कहा, विप्रो में, कर्मचारियों का कल्याण, गरिमा और सम्मान सर्वोपरि है। हम किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, भेदभाव, उत्पीड़न या ऐसे कार्यों के प्रति बर्दाश्त न करने की नीति अपनाते हैं, जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि मामला की फिलहाल जांच चल रही है, इसलिए हम मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पूर्व महिला कर्मचारी ने क्या आरोप लगाए हैं?

कंपनी का यह बयान पूर्व महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद आया है, जो उसके हिंजवाड़ी कार्यालय में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर तैनात थी। पुलिस के पास दर्ज शिकायत में महिला ने कहा कि उसे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उस पर इस्तीफा देने का दबाव डाला।

आरोप

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि एक महिला सहकर्मी ने यह कहते हुए बार-बार उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला कि इससे उसकी जीवनशैली और भविष्य के अवसर बेहतर होंगे। उसने यह भी आरोप लगाया कि सहकर्मी ने उसे एक मुस्लिम परिचित से संबंध बनाने और हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

सहकर्मी पर नहीं की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई- शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कई बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद सहकर्मी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उनके वकील विवेक भोसले ने आरोप लगाया कि उनका इस्तीफा दबाव में और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए लिया गया था।शिकायत हिंजवाड़ी पुलिस को सौंप दी गई है, जिसने कंपनी को नोटिस जारी कर कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ बहाली, मुआवजे और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, यह मामला धार्मिक उत्पीड़न से संबंधित नहीं है।

रायपुर। जनजातीय विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्ट्रेंथनिंग आईटीडीए-आईटीडीपी में रायगढ़ जिले की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) धर्मजयगढ़ को 'बेस्ट परफॉर्मिंग आईटीडीए-आईटीडीपी' के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। इस उपलब्धि के लिए परियोजना को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई।

धर्मजयगढ़ परियोजना को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान न केवल रायगढ़ जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि राज्य शासन के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावी नीति-निर्माण, जनजातीय कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता तथा जमीनी स्तर पर समर्पित कार्य संस्कृति को भी रेखांकित करती है। यह सम्मान जनजातीय समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों, नवाचारों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर प्रदान किया गया है।

इंडिया ब्लॉक की बैठक से डीएमके ने बनाई दूरी

नईदिलील। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है। यह तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद हुए नाटकीय राजनीतिक बदलाव के मद्देनजर कांग्रेस के साथ डीएमके के संबंधों में आई दरार का संकेत है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने डीएमके की लंबे समय से सहयोगी रही कांग्रेस के बावजूद अभिनेता विजय की टीवीके को तमिलनाडु में सरकार बनाने में समर्थन देने का निर्णय लिया। इस कदम से डीएमके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दशकों पुरानी साझेदारी को तोड़ दिया है। यह दरार

संसद में भी दिखने लगी है। संबंधों में आई दरार का एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए, डीएमके सांसद कनिमोझी ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर डीएमके सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया। इस कदम को व्यापक रूप से इंडिया ब्लॉक के भीतर दरार की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया।

विपक्षी इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता 8 जून को राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबलों से पहले विपक्षी समन्वय को मजबूत करने के लिए बैठक करेंगे। संविधान क्लब में होने वाली इस बैठक में लगभग 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह बैठक हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक के दो प्रमुख घटक दलों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके की करारी हार के मद्देनजर हो रही है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी के इस महत्वपूर्ण विपक्षी बैठक में शामिल होने की संभावना है, जबकि पार्टी अभूतपूर्व आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रही है और उसके अधिकांश विधायक नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बनर्जी द्वारा टीएमसी नेताओं पर कथित हमलों का मुद्दा उठाने और इस मामले पर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों से समर्थन मांगने की भी संभावना है।सूत्रों के अनुसार, बैठक में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे शामिल हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही सार्वजनिक रूप से इंडिया ब्लॉक से खुद को अलग कर चुकी है।

प्रमुख समाचार

मोहन भागवत चार जून से पांच दिन के राजस्थान प्रवास पर

राजस्थान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत चार से पांच दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। चार जून को करौली के हिंडौन से प्रवास की शुरुआत होगी। प्रवास को लेकर क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने जानकारी दी।क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने

बताया कि ग्रीष्मावकाश में कार्यकर्ताओं के शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए तीन सप्ताह के संघ शिक्षा वर्गों का आयोजन होता है। इसमें प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण करने के बाद में एक से अधिक शाखाओं की देखरेख करने वाले कार्यकर्ताओं का द्वितीय वर्ष कैंप क्षेत्र के अनुसार होता है। इस साल राजस्थान में दो स्थानों पर द्वितीय वर्ष का आयोजन हो रहा है। द्वितीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग में एक बार सरसंघचालक और अगले वर्ष सरकार्यवाह का प्रवास रहता है। इसी कार्यक्रम के तहत मोहन भागवत का राजस्थान प्रवास पांच दिन के लिए तय हुआ है। सरसंघचालक मोहन भागवत प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम सप्ताह में चार से सात जून तक हिंडौन में शिविर में भाग लेंगे।

ममता बनर्जी ही रहेंगी सुप्रीम लीडरः सलाहकार का पद मंजूर नहीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी के बागी खेमे में महज 24 घंटे के भीतर ही असंतोष के सुर उभर आए हैं। 58 बागी विधायकों ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक दल पर

नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब ऋब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस बागी गुट में भारी बेचैनी देखी जा रही है। कई विधायकों ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी ही उनकी सुप्रीम लीडर रहेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ममता बनर्जी को महज एक सलाहकार बनाकर छोड़ा गया, तो वे इस बागी गुट में रहने पर दोबारा विचार कर सकते हैं। बागी विधायक दल के नवनिर्वाचित विपक्ष के नेता ऋब्रत बनर्जी ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद ही बागी गुट के भीतर अलग-अलग सुर दिखाई देने लगे। वे एक तरफ पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, वे टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी के साथ अपना राजनीतिक और भावनात्मक रिश्ता भी बनाए रखना चाहते हैं।

प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस

चेन्नई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तमिलनाडु से राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को अपना उम्मीदवार नामित किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, चक्रवर्ती चेन्नई सचिवालय स्थित विधानसभा सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

थिरु टीवीके विजय और टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने टीवीके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत कांग्रेस को राज्यसभा सीट आवंटित की। एक्स पर, चोडंकर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु के सीएम विजय का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राज्यसभा की रिक्त सीट भारतीय कांग्रेस संघ को आवंटित की। यह उदारतापूर्ण कदम गठबंधन धर्म, सहयोगी दलों के बीच आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक सशक्त संदेश देता है कि राजनीतिक सहयोग विश्वास, समझ और जनता के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित हो सकता है।

लोकसभा में अभिषेक बनर्जी को नेता पद से हटाने की तैयारी

कोलकाता/ नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस में फूट के बाद अब लोकसभा में बागी गुट अपना नेता चुनने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी में कभी दूसरे नंबर के नेता रहे अभिषेक बनर्जी आज पार्टी के भीतर अलग-थलग पड़ गए हैं। लोकसभा में पार्टी नेता के रूप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

की तैयारी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के अंदरखाने यह बात चल रही है कि तृणमूल की संसदीय दल की बैठक बुलायी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि कई सांसद बागी गुट के संपर्क में नहीं हैं। दिल्ली की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, यह देखना बाकी है। पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि पार्टी के मशहूर सांसद ममता से दूरी बढ़ा रहे हैं। कल्याण-काकली विवाद पर दबाव कम नहीं हुआ है। काकली ने खुद कल्याण के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखे हैं। अब क्या अन्य सांसद भी मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी के खिलाफ काकली के आरोपों से सहमत होंगे।

दक्षिण-पश्चिम मानसून विलंब से केरल पहुंच गया

नईदिल्ली। देशभर में भीषण गर्मी के बीच आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया, जिसके साथ ही देश में चार महीने तक चलने वाले वर्षा ऋतु की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आमतौर पर मानसून एक जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस

बार इसकी एंट्री कुछ दिनों की देरी से हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। हालांकि मौसम संबंधी परिस्थितियों में बदलाव के कारण इसकी प्रगति धीमी रही और अब चार जून को मानसून ने केरल में प्रवेश किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मानसून ने केवल केरल ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के शेष हिस्सों, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों, कोमोरिन क्षेत्र तथा बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में भी आगे बढ़त दर्ज की है।

चांदी बाजार का महाघोटाला : 99.9% शुद्ध चांदी सिर्फ 65% असली है?

मुंबई। भारतीय सर्राफा बाजार इस समय नए संकट का सामना कर रहा है। ज्वेलरी बाजार में चांदी का बीटूबी (बीटूबी कंपनी) और बीटूसी (बिजनेस टू कंज्यूमर) व्यापार प्रभावित हो रहा है। जिसकी मुख्य वजह चांदी की शुद्धता पर उठ रहे सवाल हैं। ज्वेलर्स और डीलरों का कहना है ग्राहक जो चांदी लेकर बेचने आते हैं उसमें केवल 65 से 70 प्रतिशत ही शुद्ध चांदी होती है। मुंबई के बाजार में प्रतिदिन औसतन 1000 से 1500 किलोग्राम की चांदी बिकती है, लेकिन इसकी वजह से सौदे में कमी आ रही है औसतन 10 प्रतिशत भी नहीं हो रहे हैं। यही समस्या सिक्के, कटलरी उत्पादों और बर्तन वाले ज्वैलर्स को भी उठानी पड़ रही है।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक प्रवक्ता और उमेदमल त्रिलोकचंद ज्वैलर्स के कुमान जैन बताते हैं, अगर ग्राहक चांदी खरीदने आते हैं, तो उन्हें किलो असली चांदी मिलेगी, लेकिन बार और सिक्को में केवल 65 से 70 प्रतिशत ही चांदी मिलती है, बाकी उत्पादों में दूसरी धातु मिलाकर, जरूरत के हिसाब से लेते हैं। इसकी वजह से इन सौदों में गिरावट आ रही है। सरकारी रोक के बाद, 30 किलोग्राम आयातित चांदी के बार से होने वाली आय न के बराबर रह गई है। अभी .999 टच (कैरेट) चांदी की कीमत बिना जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के करीब 2.63 लाख रुपये है, वहीं बिल में बिना 3 प्रतिशत जीएसटी के 8 से 10

प्रतिशत डिस्काउंट के साथ करीब 2.5 लाख रुपये में मिल रही है।

मुंबई के मेघाजी वानेचंद बुलियन डीलर के अनिल संघवी कहते हैं, कच्चे चांदी को रिफाइनरी में पिघलाकर उससे एक किलो या उससे भी कम वजन की छड़े तैयार की जाती है और बाजार में बेची जाती हैं। जिसमें बेईमान व्यापारी 0.999 कैरेट का सिक्का छापने पर जोर देते हैं। जिसमें उपभोक्ता और व्यापारियों को किलोग्राम वजन के आधार पर गुमराह कर मुनाफ कमा सकें। देखा जाए तो कैरेट से शुद्धता को विशेष संबंध नहीं होता है। इसके बाद जब इसी चांदी को बेचा जाता है, तो यह उपभोक्ता को भारी नुकसान होता है।

लंदन बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के विश्लेषक पैनल में भारतीय प्रतिनिधि भार्गव वैद्य ने कहा, पांच साल पहले रिसाइकल चांदी में चांदी की शुद्धता 85 प्रतिशत थी, यह आज घटकर केवल 55 से 70 प्रतिशत रह गई है। इसका मतलब है कि आप शुरुआत से ही व्यापारी को भारी मुनाफा देते हैं, कीमतों में यदि 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाती है तब ही ग्राहक इसका फायदा होता है। वे कहते हैं, भारत में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह समस्याएं और गंभीर होती जा रही हैं। भारत अपनी कुल जरूरत का 80 प्रतिशत यानी 7000 टन चांदी सालाना आयात करता है। इसके विपरित चांदी की शुद्धता को आधिकारिक रूप से सत्यापित करने के लिए भारत में केवल 286 हॉलमार्किंग केंद्र हैं। हाल ही में चांदी की औद्योगिक मांग भी काफी बढ़ गई है। आपूर्ति के अधिकांश दरवाजे बंद होने की वजह से वैश्विक बाजार में अशुद्ध चांदी 10 से 12 प्रतिशत से अधिक कीमत पर बिक रही है।

अनिल संघवी और कुमार जैने का कहना है कि नियामक सरकारी संगठनों को इस संबंध में तत्काल लाइसेंस जारी करने चाहिए। कीमती धातु शोधक संघ ने इस संबंध में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। हमारी यह मांग तो कई वर्षों से चली आ रही है कि, चांदी आभूषणों में हॉलमार्किंग और शुद्धता के सभी मानक वैश्विक स्तर पर भी अनिर्वाय किए जाने चाहिए। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को अपने नेटवर्क का विस्तार करने की जरूरत है। सोने की रिफाइनरियों की तरह चांदी की रिफाइनरियों को भी मान्य प्राप्त अनिर्वाय लाइसेंस दिए जांए और चांदी की शुद्धता जांच के लिए केंद्रों को शुरू किया जाने की आवश्यकता है।

मोर गांव-मोर पानी अभियान से जल संरक्षण को मिली नई मजबूती

एमसीबी जिले में प्रतिदिन 20 हजार श्रमिकों को मिल रहा रोजगार,

12.83 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत

एमसीबी। एमसीबी जल संरक्षण, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ते हुए मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मोर गांव-मोर पानी अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत जिले में प्रतिदिन औसतन 20 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ भविष्य के जल संकट से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन में जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बड़े पैमाने पर रोजगारमूलक कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

इन कार्यों पर लगभग 12 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है। स्वीकृत कार्यों में नवीन तालाब निर्माण एवं गहरीकरण, आजीविका डबरी (खेत तालाब), परकोलेशन टैंक, अर्दन चेक डैम, जल संग्रहण संरचनाएं तथा भू-जल पुनर्भरण आधारित विभिन्न कार्य शामिल हैं।

इन संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भू-जल स्तर में सुधार आएगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। मनरेगा के तहत संचालित कार्यों से हजारों ग्रामीण श्रमिकों को अपने गांवों में ही रोजगार मिल रहा है। इससे मजदूरों को पलायन किए बिना स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। साथ ही ऐसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों तक ग्रामीण समुदाय को मिलता रहेगा। जिला प्रशासन का मानना है कि जल संरक्षण आधारित ये कार्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि भविष्य में संभावित जल संकट से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनसे पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास की नई संभावनाएं विकसित होंगी।

इंदिरा वार्ड क्रमांक-16 में कांग्रेस को मिली जीत

भाजपा प्रत्याशी को 436 वोटों से हराया

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के इंदिरा वार्ड क्रमांक-16 में 3 दिन पहले उपचुनाव हुआ था। जहां 4 जून की सुबह दोनों प्रत्याशी अपनी किस्मत को जानने पहुँचे। जहाँ कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित करते हुए भाजपा प्रत्याशी को 436 वोटों से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ कांग्रेस ने वर्षों से कायम अपने सीट को सुरक्षित रखा यह उपचुनाव पूर्व पार्षद अब्दुल रशीद के निधन के बाद हुआ। करीब 23 वर्षों तक इस वार्ड में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, जिसे इस बार भी पार्टी ने बरकरार रखा। अब्दुल रशीद के करीबी रहे रामकृष्ण तिवारी ने इस विरासत को संभालते हुए जीत दर्ज की। चुनाव मुकाबला तिवारी बनाम तिवारी के रूप में चर्चित रहा, जहां कांग्रेस के रामकृष्ण (मुन्नू) तिवारी ने भाजपा के मनोहर दत्त तिवारी को स्पष्ट अंतर से पराजित किया। वार्ड में कुल 1542 मतदाताओं में से 1229 ने मतदान किया, जिससे मतदान प्रतिशत 79.7त्न रहा। बूथ क्रमांक 1 में 666 और बूथ क्रमांक 2 में 563 वोट डाले गए। बूथ 1- कांग्रेस 483, भाजपा 157, आप 18, नोटा- 5, बूथ 2 - कांग्रेस- 331, भाजपा- 221, आप- 4, नोटा- 4, कुल मतों की बात करें तो कांग्रेस के मुन्नू तिवारी को 814 वोट मिले, जबकि भाजपा के मनोहर दत्त तिवारी को 378 वोट प्राप्त हुए। इस तरह कांग्रेस ने 436 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की इस चुनाव को विकास बनाम परंपरा की जंग के तौर पर देखा गया, जिसमें कांग्रेस ने एक बार फिर परंपरा को कायम रखते हुए जीत अपने नाम की। जीत के बाद कांग्रेसियो ने बाइक रैली निकालने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिथलेश स्वर्णकार से मिलने पहुँचे। जहाँ उनका आशीर्वाद लेने के बाद माँ दंतेश्वरी मंदिर पहुँच माँ का आशीर्वाद लिया गया। वही वार्डवासियों के द्वारा जताए गए भरोसे पर पूर्णरूप से खरा उतरने की बात कहते हुए वार्ड के लिए 24 घंटे सेवा देने की बाद भी कही गई।

अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

वन भूमि पर बने 34 मकानों को किया ध्वस्त

बलरामपुर। जिले में वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर वन भूमि पर बने 34 अवैध मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई को वन भूमि संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, वन भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन द्वारा पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर 34 मकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

महादेव एप मनी लॉन्ड्रिंग मामला: हाईकोर्ट ने दी फ्रीज शेयर बेचने की अनुमति

लेकिन रकम पर कंपनियों का नहीं होगा अधिकार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फ्रीज किए गए करीब 423 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों और डीमैट खातों की वैल्यू सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है और यदि फ्रीज किए गए शेयरों की कीमत गिरती है तो इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपने दिए गए फैसले में कंपनियों को यह छूट दी है कि वे फ्रीज किए गए शेयरों को बेचकर प्राप्त रकम को ईडी की निगरानी में सुरक्षित म्यूचुअल फंड या सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी राशि ईडी के नियंत्रण में ही रहेगी और कंपनियां उसे निकाल नहीं सकेंगी। बता दें कि ईडी ने वर्ष 2022 में महादेव ऑनलाइन बुक सट्टा एप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच के दौरान एजेंसी को जानकारी मिली कि सट्टेबाजी से अर्जित कथित अवैध धन को कोलकाता के कारोबारी हरि शंकर टिबरेवाल और सूरज चोखानी के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में निवेश किया गया। ईडी के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल शेयर बाजार में निवेश के लिए किया गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2024 को ईडी ने कार्रवाई करते हुए आठ कंपनियों के डीमैट और ट्रेडिंग खाते फ्रीज कर दिए थे। इन खातों में मौजूद शेयरों की कुल वैल्यू 29 फरवरी 2024 की स्थिति में करीब 423.60 करोड़ रुपये आंकी गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीएमएलए कानून के तहत संपत्ति को फ्रीज या अटैच करने का उद्देश्य उसे सुरक्षित रखना होता है। केवल कागजी तौर पर अधिकार बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। यदि शेयर बाजार में गिरावट के कारण संपत्ति की कीमत कम हो जाती है तो फ्रीज करने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में यदि कंपनियां केस जीतती हैं या सरकार संपत्ति जब्त करती है, दोनों ही स्थितियों में संपत्ति की वास्तविक वैल्यू सुरक्षित रहना जरूरी है। अदालत ने यह भी माना कि ईडी कोई निवेश प्रबंधन एजेंसी नहीं है, लेकिन संपत्ति का मूल्य बचाने वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा, 3700 अभ्यर्थी होंगे शामिल

8 केंद्रों पर सुरक्षा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन आज किया गया है। इस परीक्षा के लिए जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 3700 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार सुबह 9.30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

छत्तीसगढ़ व्यापम के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैग प्रतिबंधित रहेंगे। कैलकुलेटर, इयरफोन, धात्विक वस्तुएं तथा किसी भी प्रकार की नकल सामग्री लाना पूर्णत: वर्जित है। परीक्षार्थियों को केवल नीले अथवा काले बॉल पेन के उपयोग की अनुमति होगी। साथ ही, उन्हें आधी बांह वाले सादे एवं हल्के रंग के कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना होगा। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। प्रत्येक केंद्र में हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से अनिवार्य फ्रिस्किंग की जाएगी। मैनुअल पैट-डाउन चेक और प्रवेश प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मियों द्वारा होगी।

पुरुष परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी। परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता दल और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक दल परीक्षा अवधि के दौरान सतत निगरानी करेंगे।

चोरी के मामले में सराफा कारोबारी समेत तीन पकड़ाए

गहने और सोने की बिस्किट जब्त

धमतरी। जिले के कोसमर्रा गांव में सूने मकान में हुई सोने-चांदी के गहने के साथ नगदी की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सराफा कारोबारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के गहने, 10 ग्राम सोने का बिस्किट और वारदात में इस्तेमाल की गई कुदाली बरामद की गई है। यह घटना भखारा थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम कोसमर्रा निवासी कृष्ण कुमार कोसरे 13 मई को अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने अभनपुर गए हुए थे। इसी दौरान उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार जब 17 मई को वापस लौटा, तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने भखारा थाना में मामला दर्ज कराया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संदेही घनश्याम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने अपने साथी हेमंत उर्फ सोनू मानिकपुरी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कही। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मकान का ताला और आलमारी का लॉक तोड़कर जेवरात सहित नगदी चोरी की थी। चोरी के बाद दोनों ने जेवरात आपस में बांट लिए और नगदी खर्च कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद किए। वहीं यह भी खुलासा हुआ कि चोरी के सोने के गुलबंद हार को रायपुर निवासी सराफा कारोबारी ओमप्रकाश सोनी को दिया गया था, जिसने उसे गलाकर 10 ग्राम का सोने का बिस्किट बना दिया था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बस से पकड़ा गया 2 करोड़ रुपए का 20 क्विंटल गांजा

सूरजपुर। गांजा तस्करी के लिए तस्कर अनोखे-अनोखे तरीके अपनाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में बस के जरिए परिवहन किए जा रहे 2 करोड़ रुपए कीमत का 20 क्विंटल 'हरा सोना' पुलिस ने जब्त किया है। जानकारी के अनुसार, जयनगर थाना क्षेत्र के सिलफिली में बस के जरिए गांजा का परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिली कि नीलम ट्रांसपोर्ट की बस अंबिकापुर से मध्यप्रदेश के कटनी जिला जा रही थी। बस में झाड़ू की आड़ में टोकरी में रखकर ले जाए जा रहे 20 क्विंटल गांजा को पुलिस ने 112 की मदद जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह बात सामने आई कि परिवहन का कोई भी साधन तस्करों से नहीं बचा है। इसके लिए किसी भी भी जरिया बनाया जा सकता है। बहरहाल, पूरे वाकये में अच्छी बात यह रही कि बस का सहारा लेने के बाद भी तस्कर गांजा की तस्करी में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अब उन्हें तस्करी के लिए कोई और दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी।

ग्राहक बनकर पहुंचे आबकारी अफसर ने किया भंडाफोड़

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मुंगेली शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और भोजनालयों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान मुंगेली बस स्टैंड के समीप संचालित एक बिरयानी सेंटर में ग्राहक बनकर पहुंचे आबकारी अधिकारियों ने अवैध शराब बिक्री का भंडाफोड़ किया। जानकारी के अनुसार, टीम ने पहले सामान्य ग्राहक की तरह बिरयानी सेंटर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान वहां अवैध रूप से शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद मौके पर कार्रवाई करते हुए 18 नग पाव गोवा व्हिस्की, कुल 3.24 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। मामले में संचालक के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

एनडीपीएस केस में रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल

दुर्ग। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी पक्ष से कथित रूप से पैसों की मांग करने के आरोप में दो सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ एसआई तुलसीराम साहू और खुर्सीपार थाना में पदस्थ एसआई देव लाल साहू शामिल हैं। दोनों को निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग अटैच किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें तीन दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एसआई तुलसीराम साहू ने रज्जी कौर नामक महिला को 5.80 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि महिला को छोड़ने के एवज में उसकी बेटी से 50 हजार रुपए की मांग की गई थी। महिला की बेटी जसबीर का आरोप है कि उसने पहली बार में 20 हजार रुपए देने की बात स्वीकार की थी और राशि भी दी गई थी।

सूरजपुर के शिवनंदनपुर नपं चुनाव में बीजेपी की जीत

सूरजपुर। जिले की नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के पहले चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। आम निर्वाचन के परिणाम घोषित हो गए हैं, अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 362 मतों से हरा दिया है। चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मतगणना के दौरान अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल को कुल 2028 वोट मिले। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 1666 मत मिले। इस तरह भाजपा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाते हुए नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष का ताज अपने नाम किया है। ये जीत यहां के विकास की जीत है और जनता की जीत है, हर मोहल्ले-वार्ड में आगे विकास दिखेगा- लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्रीवहीं 15 वार्डों में हुए पार्षद चुनाव के परिणामों में कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस ने 15 में से 8 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के उम्मीदवार 7 वार्डों में विजयी रहे।

खैरागढ़ में करोड़ की बेशकीमती जमीन पर किसका दावा

खैरागढ़। शहर की बहुचर्चित एडवर्ड चिल्ड्रेन पार्क और नजूल भूमि को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। 52 साल पहले हुई जमीन की रजिस्ट्री को आधार बनाकर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर हक का दावा किया जा रहा है। निजी स्वामित्व के दावों के उलट राजस्व और नजूल अभिलेखों में यही भूमि पार्क, घास भूमि, जंगल और सार्वजनिक उपयोग की जमीन के रूप में दर्ज है। जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वो जमीन करीब 85 हजार स्क्वॉयर फीट एरिया में है, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ है। राजस्व विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक साल 1974 में दो प्लाट जिसका नंबर 114 और 115 है, उसकी रजिस्ट्री स्मृति सिंह के नाम पर हुई थी। उस वक्त सरकारी कागजों में इन दोनों प्लाटों को एडवर्ड पार्क और बाड़ी एडवर्ड पार्क के रुप में रिकार्ड में दर्ज रहा। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उस वक्त के राजा रहे वीरेंद्र बहादुर सिंह का नाम विक्रेता यानी जमीन बेचने वाले के रुप में दर्ज है। 22 भागों में जमीन बांटा गया है।

पीएमजीएसवाई की सड़कों के निरीक्षण में मिली तकनीकी खामियां

विभाग सख्त: ठेकेदार को दोबारा काम कराने के निर्देश

बीजापुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीजापुर जिले में बन रही सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रमुख अभियंता के.के. कटारे के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान कई निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए गुणवत्ता सुधारने तक भुगतान रोकने की चेतावनी दी है। निरीक्षण के दौरान भोपालपटनम विकासखंड की उलूर-केरपे सड़क का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पाया कि सड़क निर्माण में कई जगहों पर निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। सड़क किनारे खाईनुमा खुदाई कर अर्थवर्क किए जाने और मनमाने ढंग से पुलियों का निर्माण करने पर भी नाराजगी जताई गई। प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार अंकित गुप्ता को निर्देश दिए कि सभी त्रुटिपूर्ण पुलियों को तोड़कर विभागीय अभियंताओं के मार्गदर्शन में दोबारा निर्माण कराया जाए और सड़क किनारे की गई खुदाई को भरकर कटाव की आशंका समाप्त की जाए। इसी प्रकार पालनार-रेगडगट्टा मार्ग और भैरमगढ़-बीजापुर रोड से बड़ेतुंगली तक चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने और विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि बेहतर सड़क संपर्क से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बाजार तक पहुंच आसान होगी।

इबोला प्रभावित अफ्रीका से लौटे तीन यात्री होम आइसोलेशन

दो भारतीय एक युगांडा का नागरिक

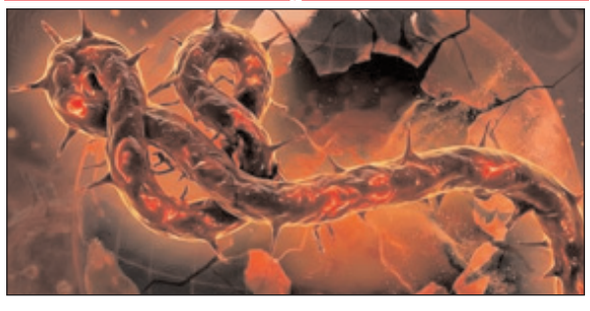

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अफ्रीका के इबोला प्रभावित देशों से लौटे तीन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि अफ्रीका के इबोला प्रभावित देशों से लौटे तीन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई को इबोला प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल% घोषित किया था। यह एहतियाती कदम 21 दिनों के लिए उठाया गया है, हालांकि इन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं हैं। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला 31 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से दुर्ग पहुंची थी। दो अन्य लोग 2 जून को इथियोपिया और युगांडा से भिलाई आए। इन यात्रियों में दो भारतीय नागरिक और एक युगांडा का नागरिक है। कलेक्टर ने आगे कहा कि उनमें लक्षण या संपर्क का कोई इतिहास नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी दिन में दो बार फोन पर उनकी निगरानी कर रहे हैं। वे सुबह-शाम उनकी सेहत की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यात्रियों को किसी भी परेशानी पर तुरंत सूचित करने की सलाह दी गई है। दुर्ग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी ने बताया। इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाता है। उन्हें रोज़ाना स्वास्थ्य निगरानी और मेडिकल सलाह दी जाती है। हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की चिकित्सकीय जांच की जा रही है। लक्षणों और संपर्क के इतिहास के आधार पर उन्हें जोखिम श्रेणियों में बांटा जाता है। मनोज दानी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को जोखिम श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 1 में बिना लक्षण और संपर्क इतिहास वाले यात्री आते हैं। दुर्ग में लौटे तीनों यात्री इसी श्रेणी 1 में हैं। इसका अर्थ है कि उनमें कोई लक्षण नहीं है और वे इबोला के मरीजों के संपर्क में नहीं आए।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री आज पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को करेंगे सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आगामी शुक्रवार 5 जून को दोपहर 2.30 बजे न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप-10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। इस गरिमामय अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक मेधावी छात्र को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा और आवागमन को सुगम बनाने के लिए दोपहिया वाहन क्रय करने हेतु 1 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। इस प्रकार प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को कुल रुपये 2,00,000/- का चेक वितरण कर लाभान्वित किया जाना है।

57 लोग मिले एचआईवी पॉजिटिव, घबराने की जरूरत नहीं : स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जांच के दौरान 57 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य हमला भी अलर्ट मोड पर आ गया है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लोगों से न घबराने की अपील की है। श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि हम केवल रायगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर एचआईवी पीड़ित लोगों की जांच कर रहे हैं, जो पॉजिटिव होकर निकलेंगे उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है, जो युथ नशीली दवाईयों को नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उनपर प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई भी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज और परिवार के लोगों को भी इस पर जागरूक होना पड़ेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता बढ़ाएं- राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से गुरुवार को लोकभवन में रायपुर वन वृत्त के संभागीय वन अधिकारी मयंक पाण्डेय ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित न रहकर सतत सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

बढ़ईपारा इलाके के किराना दुकान में लगी अचानक आग, कोई हताहत नहीं

रायपुर। बढ़ईपारा इलाके में गुरुवार सुबह एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने दुकान के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया जिससे दुकान में रखे किराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों कर फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नुकसान का वास्तविक आंकलन आग पूरी तरह बुझने और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे किराना दुकान बंद था और इसी दौरान दुकान के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने दुकान के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आग लगने से दुकान में रखे किराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यह दुकान कुमार नामक कारोबारी की है।

पिच्चेकट्टा जलाशय के कार्यों के लिए 4.85 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-भानुप्रतापपुर के पिच्चेकट्टा जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 85 लाख 2 हजार रुपए स्वीकृत किए गए है। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण हाने पर क्षेत्र के किसानों को कुल 364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। योजना के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

राजनांदगांव जिला चिकित्सालय उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रणी

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 6.42 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

■ **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास सराहनीय, जिला चिकित्सालय को और सुविधाओं से किया जाएगा सुसज्जित**

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मजबूत अधोसंरचना विकसित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में स्वास्थ्य अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए 6 करोड़ 42 लाख 70 हजार रुपए की लागत से किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने 3 करोड़ 56 लाख 70 हजार रुपए की लागत से निर्मित जिला चिकित्सालय भवन के प्लिंथ अपग्रेडेशन एवं ऊंचाई विस्तार कार्य का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

जिला चिकित्सालय एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले मरीजों की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सक्रियता और सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राजनांदगांव जिला चिकित्सालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। राजनांदगांव जिले में इस दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिले की मातृ मृत्यु दर राज्य के औसत से कम होना एक सुखद संकेत है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में छत मरम्मत, लिफ्ट सुधार कार्य, जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से दो स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति, डेंटल एक्स-रे मशीन एवं सेपरेटर मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की घोषणा की। साथ ही राज्य बजट से अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिला चिकित्सालय अब नए स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं के साथ जिलेवासियों को समर्पित हुआ है। उन्होंने चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि अस्पताल में आवश्यक उन्नयन कार्यों के पूर्ण होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला चिकित्सालय की टीम का दायित्व है कि वह समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करे। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला चिकित्सालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले में हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

कार्यक्रम में महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह, समाजसेवी श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री गौतम पारख, जीवनदीप समिति के सदस्यगण, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. पंकज लुका, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, सिविल सर्जन डॉ. महेन्द्र प्रसाद, एसडीएम श्री गौतम पाटिल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

एनईपी के सपनों को साकार करेगी व्यावहारिक शिक्षा

रट्टू ज्ञान की जगह कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत: उच्च शिक्षा मंत्री

रायपुर। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री टंक राम वर्मा ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अद्यतन पाठ्यक्रम पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी पुस्तक मानचित्र निर्माण के सिद्धांत : का विमोचन किया। उच्च शिक्षा एवं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली इस बेहद उपयोगी पुस्तक का लेखन प्रदेश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. राजू चंद्राकर और डॉ. लोकेश पटेल द्वारा किया गया।

विमोचन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने दोनों विद्वान लेखकों को उनके इस उत्कृष्ट अकादमिक कार्य के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक विद्यार्थियों को मानचित्र कला जैसी महत्वपूर्ण विधा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं को सरलता से समझने में अत्यंत सहायक और उपयोगी सिद्ध होगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और मातृभाषा व सरल भाषा में ऐसी उच्च स्तरीय अकादमिक पुस्तकों का आना एक सराहनीय कदम है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रख्यात समाजसेवी एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री जागेश्वर यादव ने भी इस उत्कृष्ट अकादमिक कार्य के लिए दोनों लेखकों को अपनी आत्मीय शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लेखकों के भगीरथ प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा, ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयास समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी को एक नई, सकारात्मक और प्रगतिशील दिशा प्रदान करते हैं।

पुस्तक के लेखक डॉ. राजू चंद्राकर और डॉ. लोकेश पटेल ने इस अवसर पर बताया कि इस पुस्तक को विशेष रूप से नई शिक्षा नीति (हश्वक्क) के मापदंडों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भूगोल और मानचित्रण के जटिल व तकनीकी सिद्धांतों को बहुत ही सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में आधुनिक मानचित्र निर्माण की तकनीकों, अक्षांश-देशांतर के व्यावहारिक उपयोग और भौगोलिक आंकड़ों के सटीक प्रस्तुतीकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

पीएम आवास योजना (शहरी): राज्य स्तरीय स्वीकृति व निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने एसएलबीसी के बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को उनके हिस्से की राशि के लिए ऋण देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करें, जिससे हितग्राही आवास शीघ्रता से बना सकें। मुख्य सचिव ने नगरीय-प्रशासन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत हुए हैं, उनके लिए एक विशेष शिविर लगाकर बैंकर्स से ऋण दिलवाये। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि हितग्राहियों को दी जाती है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास निर्माण के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज हितग्राहियों की प्रविष्टी में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु भौतिक प्रगति अनुसार केन्द्रांश राशि एक लाख 50 हजार रूपए तथा अनिवार्य राज्यांश की राशि एक लाख रूपए दी जाती है। हितग्राही द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास पूर्ण करते हुए गृह प्रवेश करने पर राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के अंतर्गत प्रति आवास 32 हजार 850 रूपए पृथक से हितग्राही के खाते में हस्तांतरित की जायेगी। प्रति आवास डीपीआर और पीएमसी शुल्क की राशि 6 हजार 150 रूपए राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक अंतर्गत 10 हजार 549 हितग्राही हेतु नवीन आवास निर्माण के लिए केन्द्रांश राशि 158 करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए तथा राज्यांश 146 करोड़ 63 लाख 11 हजार रूपए एवं हितग्राही अंशदान राशि 105 करोड़ 49 लाख शामिल करते हुए 144 नगरीय निकायों में 410 करोड़ 35 लाख 61 हजार रूपए की लागत की 114 परियोजनाओं को स्वीकृत करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों की शांति व आर्थिक प्रगति से बौखलाई कांग्रेस: भाजपा

■ **प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने बस्तर में स्थानीय रोजगार के अवसरों में इजाफे की दिशा में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की**

रायपुर। कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ एक वोट बैंक की तरह किया है। आज जब बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में शान्ति लौट रही है और आर्थिक प्रगति हो रही है, तो कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है और अब क्षेत्र में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने में जुट गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के आर्थिक और समग्र विकास के लिए सिर्फ 5 साल का वक्त मांगा है। भाजपा सरकार बस्तर के जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक को मजबूत करते हुए वहाँ विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने गुरुवार को पत्रकारवार्ता में कांग्रेस पर टूलकिट एजेण्डा चलाने और अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने का सीधे शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर अंचल से नक्सलियों के खात्मे के बाद अब कांग्रेस एक नई साजिश रच रही है। कांग्रेस ने एक विशेष टूलकिट तैयार की है, जिसके जरिए वे आदिवासी क्षेत्रों में भ्रम और अशांति फैलाकर अर्बन नक्सलवाद को दोबारा हवा दे रहे हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज के जीवन में आर्थिक समृद्धि आए या उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार हो। बस्तर में आर्थिक क्रांति और स्थानीय रोजगार के अवसरों में इजाफे की दिशा में किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए श्री ठाकुर ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में मिलने वाली मीठी इमली (जो पूरे एशिया में केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है), महुआ और बाँस के लिए विशेष फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आदिवासी समाज के हाथों को रोजगार देना है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उन्नत किसान बन सकें।

ठाकुर ने दो टूक कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, भाजपा सरकार बस्तर में शांति व्यवस्था और आदिवासियों के आर्थिक विकास को रुकने नहीं देगी। भाजपा आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के सही उपयोग के जरिए बस्तर को एक विकसित और उन्नत संभाग बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में अभनपुर का कारोबारी गिरफ्तार

रायपुर। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभनपुर के कारोबारी जयप्रकाश गांधी को गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया है। एक दिन पहले ही ईडी ने मुख्य आरोपी हरमीत सिंह खनूजा समेत चार लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया था। आरोप है कि हरमीत सिंह खनूजा ने जमीन दलालों के साथ मिलकर घोटाला किया और किसानों को मुआवजे की आधी राशि ही दी, जबकि बाकी रकम खुद रख ली।

27 अप्रैल को ईडी ने अभनपुर निवासी जयप्रकाश गांधी के घर पर छापा मारा था। टीम पहले उसके भाई गोपाल गांधी के घर पहुंची, इसके बाद जयप्रकाश और सत्यप्रकाश गांधी के घरों में भी जांच की गई। कार्रवाई के दौरान ईडी को अहम दस्तावेज और संदिग्ध ट्रांजेक्शन का ब्योरा मिला। इसके अलावा धमतरी, दुर्ग और रायपुर में भी छापेमारी की गई थी। बुधवार को ईडी ने जयप्रकाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया गया है। ईडी के अधिकारी नीरज कुमार ने 27 अप्रैल की रात अभनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।चार लोगों को ईडी ने बनाया आरोपी ईडी ने हरमीत सिंह खनूजा को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया है। हरमीत प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ा है। आरोप है कि उसने पटवारी और जमीन दलालों के साथ मिलकर घोटाला किया। किसानों की जमीन खरीदकर दस्तावेजों में बैक डेट में नाम दर्ज कराया गया। नामांतरण से लेकर भुगतान की रसीद तक बैक डेट में तैयार कराई गई। इस मामले में खेमराज कोसले, पुनउराम देशलहरे और कुंदन बघेल भी शामिल हैं।

पंचायत उप चुनाव

भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीट पर मिली सफलता

रायपुर। राज्य में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायत उपचुनावों में पांच नगर पंचायतों में सत्तारूढ भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर फतह हासिल की है। जगदलपुर और बिलासपुर नगर निगम के वार्ड चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने विजय दर्ज की।

पंचायत और निकायों में आम और उप निर्वाचन एक जून को शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। राज्य के नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 पद और पार्षद के 71 पदों के लिये चुनाव हुए थे। कुल 1,310 रिक्त पदों के लिए 96 मतदान केन्द्रों में कुल 31 हजार 928 मतदाताओं में से 27 हजार 6 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। त्रि-स्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य के 10, सरपंच के 34 और वार्ड पंच के 107 पदों के निर्वाचन के लिए बनाए गए 274 मतदान केंद्रों में कुल 1लाख 2 हजार 797 मतदाताओं में से 79 हजार 968 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

कांग्रेस ने नगर निगमों के उपचुनावों में शानदार वापसी की है। बस्तर जिले के जगदलपुर नगर निगम के इन्दिरा वार्ड (वार्ड क्रमांक 1) से कांग्रेस के रामकृष्ण तिवारी ने 436 वोटों से जीत दर्ज की। बिलासपुर नगर निगम के संजय गांधी नगर (वार्ड क्रमांक 29) से कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने बीजेपी उम्मीदवार को 1062 वोट से जीत दर्ज की।

पेट्रोल-डीजल की कमी से ऑटोमोबाइल व्यवसाय प्रभावित

■ **राडा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात**

रायपुर। प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति में आ रही कमी का असर अब ऑटोमोबाइल व्यवसाय पर भी पडने़ लगा है। इसी विषय को लेकर रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार एवं कीर्तिमान राठौर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नई दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की डिलीवरी के समय प्रत्येक वाहन में 2 से 5 लीटर पेट्रोल अथवा डीजल डालना आवश्यक होता है। इसके अलावा शोरूम एवं सर्विस संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले जनरेटरों में भी डीजल की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में ईंधन की सीमित उपलब्धता के कारण वाहन डिलीवरी एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। राडा पदाधिकारियों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि ऑटोमोबाइल डीलर्स को ड्रम अथवा कैन के माध्यम से पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि ग्राहकों को समय पर वाहनों की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

कलेक्टर गौरव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि समस्या का शीघ्र समाधान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा ऑटोमोबाइल उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर राडा की ओर से अमर पारवानी, विवेक गर्ग, कैलाश खेमानी एवं अभिनव ऋषि उपस्थित रहे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जिला - बीजापुर (छ.ग.)

// मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 05 (प्रथम) //

क्रमांक /569/निविदा/ग्रा.यां. सेवा/2026-27 बीजापुर, दिनांक 26/05/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण के कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है। मैनुअल निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि 12/06/2026 को अपरान्ह 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है, तथा निविदा दिनांक 15/06/2026 को 3.30 बजे अपरान्ह मे खोली जावेगी :-

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	ठेके की अनुमाति लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
1	जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंतर्गत प्रा. सेवा सहकारी समितियों में गोदाम सह शॉप रूम, टायलेट निर्माण कार्य धनोरा / गंगालूर / जंगला/आवापल्ली	बीजापुर भैरमगढ़ उसूर	24.13	12/06/2026

निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट-2. 13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://cg.nic.in/resworks में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 01/06/2026 को 5.30 बजे सायं से देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बीजापुर
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

जी-262701174/3

मोदी 10 जून को रचने जा रहे हैं सबसे बड़ा इतिहास

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। दस जून को वह देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस लंबे कार्यकाल को पीछे छोड़ देंगे, जिसे दशकों तक भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत अध्याय माना जाता रहा। मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी दस जून 2026 तक लगातार चार हजार 399 दिनों तक देश का नेतृत्व कर चुके होंगे, जबकि नेहरू का लगातार निर्वाचित कार्यकाल चार हजार 398 दिनों का था। यह केवल समय का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप का प्रतीक भी है। एक ओर नेहरू का दौर था, जब कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के सहारे लगभग निर्विरोध सत्ता में थी, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का उदय बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल में हुआ। मोदी ने पहले गुजरात में लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता साबित की और फिर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल 2014 भारतीय राजनीति का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीन दशकों बाद किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत दिलाया। कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट गई और देश में गठबंधन युग की राजनीति को निर्णायक चुनौती मिली। इसके बाद 2019 में भाजपा ने और भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए तीन सौ तीन सीटें हासिल कीं। वर्ष 2024 में भले ही पार्टी अपने दम पर बहुमत से थोड़ी दूर रही, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर सत्ता बरकरार रखी। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले हुए जिन्हें दशकों तक असंभव माना जाता था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, ऐसे ऐतिहासिक कदम रहे जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। भाजपा समर्थकों का मानना है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के संतुलन ने मोदी को देश की जनता के बीच असाधारण स्वीकार्यता दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व स्तर पर भी उनकी पहचान एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में बनी है। विभिन्न वैश्विक सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता दुनिया के कई लोकतांत्रिक नेताओं से कहीं अधिक दर्ज की जाती रही है। डिजिटल माध्यमों पर भी उनकी पहुंच अत्यंत प्रभावशाली है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित कर एक नई राजनीतिक शैली की शुरुआत सबसे पहले की थी, जिसका उन्हें भरपूर लाभ मिला। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का भौगोलिक विस्तार भी अभूतपूर्व रहा है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवल सात राज्यों में सत्ता में था, जबकि अब यह संख्या 21 हो चुकी है। पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी तथा दक्षिण भारत तक भाजपा ने अपने संगठन और जनाधार को मजबूत किया है। संसद में भी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भाजपा की उपस्थिति पहले की तुलना में कई गुना मजबूत हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लंबा कार्यकाल केवल राजनीतिक स्थायित्व का उदाहरण नहीं, बल्कि बदलते भारत की नई पहचान भी बन गया है। उन्होंने भारतीय राजनीति की भाषा, शैली और प्राथमिकताओं को बदलते हुए विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें समकालीन भारत का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया है।

तृणमूल कांग्रेस में दो फाड़ की इनसाइड स्टोरी

अभिनय आकाश

दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में, चाणक्यपुरी इलाके में स्थित %बंग भवन% के भीतर एक अलग ही सियासी तपिश महसूस की जा रही थी। यह पश्चिम बंगाल सरकार का वही आलीशान ऑफिशियल स्टेट गेस्ट हाउस है, जो दिल्ली आने वाले सूबे के मंत्रियों, अफसरों और रसूखदार नेताओं का ठिकाना बनता है। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, शुभेंदु अधिकारी अपने पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली उनकी अहम मुलाकात में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए उनका काफिला सीधे बंग भवन आकर रुका। शुभेंदु जैसे ही भीतर दाखिल हुए, वहां का माहौल अचानक भारी हो गया। सामने खड़े थे तृणमूल कांग्रेस के विधायक ऋब्रत बनर्जी। सियासत के दो अलग-अलग किनारों पर खड़े इन दो दिग्गजों की नजरें जब एक-दूसरे से मिलीं, तो बंग भवन के उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ को भी अंदाजा नहीं था कि बंद दरवाजे के पीछे चल रही इस मुलाकात की स्क्रिप्ट क्या रंग लाने वाली है। यह कोई साधारण शिष्टाचार भेंट नहीं थी। दिखने में यह महज दो नेताओं की औपचारिकता लग रही थी, लेकिन इस एक मुलाकात ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में वो बारूद बिछा दिया था, जिसका धमाका ठीक 13 दिन बाद होने वाला था। यहीं कुछ ऐसी बात हुई जिसकी कहानी आज हिंदुस्तान के सामने है कि कैसे टीएमसी महीने भर में ही टूट गई वो टीएमसी और वो ममता बनर्जी 15 सालों तक जिनकी बंगाल में सरकार थी। बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक दावा किया था कि पहले बंगाल में बीजेपी को हराऊंगी और फिर 2029 में दिल्ली पहुंचकर बीजेपी को भगाऊंगी। लेकिन आज उनके सामने रास्ते बहुत कठिन है। बंगाल में टीएमसी की टूट की कहानी कुछ ना कुछ मिलती है महाराष्ट्र से भी। टीएमसी बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने सालों साल जो उत्पात मचा रखा था उसके बाद अब पार्टी में बगावत हो रही है।

बंगाल का इतिहास जो कहता है कि यहां जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है फिर उसकी वापसी बड़ी मुश्किल होती है। इतिहास पलट कर देखिए। कांग्रेस गई तो फिर पहले जैसी कभी नहीं बन पाई। 34 सालों तक राज करने वाली सीपीएम जब बाहर हुई तो आज तक अपने पैरों पर दोबारा नहीं खड़ी हो पाई। इस बार टीएमसी जो बीजेपी की 208 सीटों के सामने सिर्फ 80 सीटें पाती है। जब ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से हार जाती हैं तो सवाल टीएमसी के भविष्य को लेकर उठ रहा है। ममता बनर्जी जो एक उम्र के दायरे में जा चुकी हैं। क्या वह टीएमसी को बचा पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में वो करिश्माई नेतृत्व है जो टीएमसी को रोक सकता है? अभी हाल ही में एक वाक्या सामने आया था जब अभिषेक बनर्जी को अंडे पड़ रहे थे। पत्थर मारे जा रहे थे। टीएमसी इसे बीजेपी के साजिश कह रही थी। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के विरोधी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी के कुकर्मों का नतीजा है। जो सालों साल उन्होंने बंगाल में उत्पात मचा रखा था। वो टीएमसी जो 15 सालों बाद सरकार से बाहर होती है। अब जिसके सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। विधायक बैठकों से गायब है। बगावत की चर्चाएं तेज हैं। ममता बनर्जी को सड़क पर उतर कर पार्टी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

टीएमसी ने भी कभी 34 साल पुरानी सीपीएम सरकार को जो सत्ता से उखाड़ा था तो उसको खत्म कर दिया था। अब यही चिंता टीएमसी को सता रही है। चुनाव हारने के बाद टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज बीजेपी नहीं है बल्कि अपनी ही पार्टी को संभाल कर रखने की दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसने यह साफ कर दिया कि चुनावी हार का असर सिर्फ विधानसभा की सीटों तक सीमित नहीं है बल्कि पार्टी के भीतर महसूस किया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगा जब 1998 में टीएमसी बनने के समय से ममता बनर्जी के साथ रही सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया।

भाजपा के कुछ वर्गों को पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व में कम्युनिस्ट दलों के पुनरुत्थान की चिंता है, लेकिन क्या वामपंथियों में वास्तव में ऐसा करने की क्षमता है? 2011 में टीएमसी द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने और 2019 के बाद भाजपा की ओर भारी संख्या में मतदाताओं के पलायन के बाद, वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर अपने पुनरुत्थान के पहले बड़े संकेत दिखा रहा है। सीपीआई (एम) ने डोमकल विधानसभा सीट जीती और फाल्टा पुनर्चुनाव में 40,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। यह सक्रिय रूप से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहा है और कार्यालयों को फिर से खोल रहा है। वाम दल जमीनी स्तर पर काफी सक्रिय हो गया है और सीआईटीयू जैसे संगठनों के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर फेरीवालों को हटाने के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है, जबकि टीएमसी लगभग निष्क्रिय रही है। जमीनी स्तर पर इस गति को बनाए रखना वामपंथ के लिए वास्तविक राजनीतिक प्रासंगिकता हासिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब टीएमसी आंतरिक दरारों से जूझ रही है जिससे जन आंदोलनों के लिए लोगों को लामबंद करने की उसकी क्षमता कमजोर हो गई है। हालांकि, इन स्थानीय लाभों को भाजपा के खिलाफ एक विश्वसनीय चुनौती में बदलने के लिए एक व्यापक रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता होगी। प्रमुख विपक्षी दल बनने के लिए, वाम को टीएमसी के मतदाता आधार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में करना होगा, जैसा कि भाजपा ने हाल के चुनावों में किया था। भट्टाचार्य ने कहा कि हालांकि वाम-कांग्रेस गठबंधन दक्षिणी पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक और हिंदू मतदाताओं को विश्वसनीय रूप से अपनी ओर खींच सकता है, वाम मोर्चे को संभावित दलबदलुओं को नाराज करना बंद करना होगा। वाम ने अब तक अपनी अधिकांश ऊर्जा टीएमसी पर हमला करने में लगाई है। अब उसे अपनी ऊर्जा भाजपा पर केंद्रित करनी होगी। वाम को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि टीएमसी समर्थक उन पर हमला करते रहने से दल बदल लेंगे। अंततः, वामपंथ का पुनरुत्थान भगवा खेमे के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में खुद को स्थापित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए, पार्टी को सभी दलों के आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों की सक्रिय रूप से रक्षा करनी होगी। वामपंथ का पुनरुत्थान कोई निश्चित बात नहीं है। सीपीआई (एम) और उसके सहयोगियों को टीएमसी के मतदाता आधार के कुछ वर्गों को अपने पक्ष में करना होगा, भाजपा पर सीधा हमला करना होगा और अपने कभी व्यापक रहे राज्यव्यापी संगठन को फिर से मजबूत करना होगा। फिर भी, टीएमसी के पतन के कगार पर होने के कारण, भाजपा के कुछ लोग सीपीआई (एम) के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरने और 4 मई के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने को लेकर चिंतित हैं।

किसी भी पार्टी की वापसी चुनाव के दिन नहीं चुनाव हारने के बाद शुरू होती है। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ममता बनर्जी आज भी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी वही है जो हमने कहा 76 साल की वो हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी की स्वीकारिता वही है जो ममता बनर्जी की है? क्या अभिषेक बनर्जी का संघर्ष वही है? अभिषेक बनर्जी वो प्रिंस की तरह बड़े हुए हैं। और प्रिंस की तरह बड़े होने में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसीलिए सवाल है क्या अभिषेक टीएमसी को उस तरह साथ जोड़ पाएंगे जैसा ममता ने जोड़ा था। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए रास्ता उतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। सरकार बनाना एक बात लेकिन बंगाल जैसे राज्य को लंबे समय तक पकड़े रखना यह दूसरी बात है। 1998 में पार्टी बनने के बाद शायद पहली बार टीएमसी खुद को इतने बड़े राजनीतिक संकट के बीच खड़ी पाती है। एक तरफ चुनावी हार है। दूसरी तरफ नेताओं की नाराजगी, संगठन के भीतर उठ रहे सवाल, बगावत की चर्चा, भविष्य के नेतृत्व को लेकर बढ़ती अनिश्चितता। यही वजह है कि आज चर्चा सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं बल्कि पूरी टीएमसी की हो रही है। इस पूरी कहानी में तीन सवाल बड़े हैं। पहला क्या टीएमसी चुनावी हार के बाद भी नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं को साथ रख पाएगी? 34 साल पुरानी सीपीएम सरकार को सत्ता से बाहर किया। कई बार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाए गए अनुमानों को गलत साबित किया। जेपी और मोरारजी देसाई के समय से लड़ती झगड़ती और जीतती हुई आ रही है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

हमारी समझ में आरम्भ में तो घी के बर्तनों में साठ हजार और नब्बे ही कीटाणु डाले गये होंगे जैसा कि वेद के उपर्युक्त प्रमाण से सिद्ध होता है, परन्तु उनमें से पूरे नब्बे उपचार निगरानी की शिथिलता के कारण विनष्ट होकर अन्तिम दिन साठ हजार ही दोष रहे होंगे।

सो वेद प्रमाण में आरम्भिक संख्या का उल्लेख है और पुराणों में अन्तिम संख्या बतलाई है यही द्वितीय वर्णन का अभिप्राय है।

हम पीछे लिख आये हैं कि वीर्य के बिन्दु में अगणित कीटाणु होते हैं सो अमोघरेतः सगर के आधान किये हुये गर्भ में साठ हजार कीटाणुओं का हो जाना कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। आशा है हमारे लालनीय लाला चिम्मनलाल जी अब इन साठ हजार लल्लाओं की लत में पड़ कर अपनी तबियत को व्यर्थ ही अलील न करेंगे?

सौ कौरव

धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों का वर्णन प्रायः सभी को विदित है। कहा जाता है कि गान्धारी को व्यास जी ने सौ पुत्र होने का वर दिया था तदनुसार यह सगर्भा हुई। उसी समय पाण्डवों की माता कुन्ती भी गर्भवती थी। दशवें महीने कुन्ती के उदर से युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ परन्तु गान्धारी तथैव सगर्भा बनी रही । तीन वर्ष के बाद कुन्ती ने पुनः सगर्भा होकर दूसरे पुत्र भीम को प्रसव किया, गान्धारी अब भी सगर्भा बनी रही। अपनी देवरानी के बालकों का डाह से दग्ध होकर गान्धारी ने अपने पेट को खूब पीटा जिससे वह गर्भ गिर गया। व्यास जी ने अपना वर सत्य करने के अभिप्राय से उस पतित हुये मासपिण्ड के एक सौ एक खण्डों को तथैव घृत-कुम्भों में सुरक्षित रक्खा जिससे समय पाकर दुर्योधनादि सौ पुत्र और दुःशला नाम की एक कन्या प्रादुर्भूत हुई।

क्रमशः ...

विश्व पर्यावरण दिवस

रमेश सर्राफ धमोरा

दुनिया में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कई कार्यक्रमों के जरिये प्रकृति को संरक्षित रखने और इससे खिलवाड़ न करने के लिए जागरूक किया जाता हैं। इन कार्यक्रमों के जरिये लोगों को पेड़-पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीजों के लिए जागरुक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है। इस अभियान की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य वातावरण की स्थितियों पर ध्यान केन्द्रित करने और पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव का भाग बनने के लिए लोगों को प्रेरित करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। लेकिन विश्व स्तर पर इसके मनाने की शुरुआत 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। जहां 119 देशों की मौजूदगी में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन भी हुआ था। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम जलवायु के लिए अभी है। यह थीम जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता और इसके वास्तविक, ठोस समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करती है

पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है हमारे आसपास या हमारे चारों और। आवरण का अर्थ होता है हम चारों और जिससे घिरे हैं। अर्थात पर्यावरण का अर्थ हमारे आस-पास के वातावरण से हैं। पर्यावरण पेड़-पौधों, वायु हमारे आस-पास की सभी चीजों से मिलकर बनता है। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता हैं। मानव और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैसे पेड़ों का कम होना, वायु प्रदूषण आदि मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता हैं। मानव की अच्छी बुरी आदतों का प्रभाव सीधा पर्यावरण पर पड़ता हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को पर्यावरण के प्रति सचेत करना हैं। उसका उद्देश्य पूरी प्रकृति व पर्यावरण की सुरक्षा करना हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट पृथ्वी पर मंडरा रहे तीन बड़े पर्यावरणीय संकटों जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक खाका प्रदान करती है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये मानव अस्तित्व के लिए एक स्व-निर्मित खतरा हैं। प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 90 लाख लोग असामयिक रूप से अपनी जान गंवाते हैं। लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं।

अपने पक्के दोस्त नेतन्याहू पर क्यों भड़क गए ट्रंप?

अभिनय आकाश

2 मई का दिन जब हाथों में ऊनों के सारे वाइल्ड कार्ड को थामे ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर पोस्ट की थी। इस पर लिखा था आई हैव ऑल द कार्डस। तब इसे ईरान जंग से जोड़कर देखा गया था। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए नया-नया एक प्लान बनाया था और उसी की खुशी सोशल मीडिया पर वो बांट रहे थे। अब वो प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में जा चुका है और शायद ट्रंप का यह दावा भी। तभी तो ईरान की एक धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पक्के पक्के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं बख्श रहे हैं। खबर है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया, जमकर लताड़ लगाई, बात गाली गलौज तक पहुंच गई। लेकिन क्यों? ईरान से ऐसी क्या धमकी थी जिसकी वजह से ट्रंप ने यह कदम उठाया? क्या नेतन्याहू की वजह से ईरान डील अटक जाएगी?

तुम पागल हो। अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब सब तुमसे और इजराइल से नफरत करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यह बातें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक फोन कॉल के दौरान कही। इस फोन कॉल की जानकारी एक्सिस को दो अमेरिकी अधिकारियों ने दी। नेतन्याहू की ओर से लेबनान पर करवाए जा रहे हमले से ट्रंप भड़क गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया तो दुनिया में इजराइल और अलग-थलग पड़ जाएगा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि मैंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने में मदद की। दरअसल, साल 2020 में इजराइली पीएम नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल शुरू हुआ था। नेतन्याहू पर यह आरोप थे कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कुछ बड़े बिजनेसमैन से महंगे गिफ्ट्स लिए हैं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर से भी गिफ्ट्स लिए हैं और बदले में उन्हें फायदा पहुंचाया। साथ ही साथ कुछ मीडिया कंपनीज़ के साथ भी सेटिंग करके अपने पक्ष में खबरें दिखवाने की कोशिश की। नेतन्याहू इजराइल

के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन पर पद पर रहते हुए क्रिमिनल केस चला। तब ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था।

1 जून को हुई इस फोन कॉल से एक दिन पहले ही ईरान ने यह वार्निंग दे दी थी कि अगर इजराइल लेबनान में अपने ऑपरेशंस जारी रखता है तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल बेरूत पर हमले ना करें। कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है। अपने ट्रूरूप सोशल पर भी उन्होंने यह पोस्ट किया और रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि इस बातचीत में ट्रंप ने पूरी तरह दबाव बना लिया। आखिर में नेतन्याहू को बात माननी ही पड़ी और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता तैयार हो रहा है उसमें लेबनान में लड़ाई खत्म करने की बात भी शामिल है। हालांकि ट्रंप को यह भी पता था कि हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और इजराइल को अपनी रक्षा का भी हक है। लेकिन ट्रंप को लगा कि नेतन्याहू जरूरत से ज्यादा अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को एस्केलेट कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर डोनल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी इजराइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू से बहुत बढ़िया बात हुई। अब बेरूत की सड़कों पर इजराइली सैनिक नजर नहीं आएंगे। जो पहले ही जा चुके हैं वह अब लौट रहे हैं। इसी तरह मेरे प्रतिनिधियों ने हिजबुल्ला से भी बातचीत की। वह हमलों को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पोस्ट किया और लिखा कि मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई। भी मैंने उन्हें कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों हमारे लोगों पर हमले नहीं रोकेगा तो हम दोबारा बेरूत को निशाना बनाएंगे। हमारी सेना आईडीएफ दक्षिणी लेबनान ने अपना ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी रखेगी। यानी नेतन्याहू बेरूत में हमला रोकने के लिए तो मान गए लेकिन साउथ लेबनान में इजराइल हमले करता रहेगा। इस पूरे वाक्य से यह तो साफ हो गया है कि ट्रंप के लिए ईरान के साथ डील करना कितना ज्यादा जरूरी है। वो नहीं चाहते कि किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से यह डील अटक जाए। ट्रंप की इच्छा वाजिब भी है। अमेरिका के हालात इस वक्त ट्रंप की राजनीति के लिए सही नहीं है। गैस की कीमतें जंग से पहले 2 से .5 प्रति गैलन होती हैं जो अब 4.5 को भी पार कर चुकी हैं। मिड टर्म इलेक्शन भी सर पर है और जंग की वजह से ट्रंप अपनी पार्टी के अंदर भी अनपॉपुलर लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते जिससे ईरान डील से पीछे हट जाए।

ट्रम्प प्रशासन ईरान से शांति समझौते के लिए वार्ता कर रहा है। नेतन्याहू द्वारा बेरूत पर हमले जारी रखने से ट्रम्प की पूरी कूटनीति दांव पर लग गई, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क गए। नेतन्याहू की सैन्य कार्रवाइयों और नागरिकों की मौतों के कारण दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अमेरिकी जनता मिडिल ईस्ट के युद्धों से थक चुकी है। ट्रम्प भी अब अपनी बड़ी प्राथमिकताओं (जैसे चीन नीति और घरेलू अर्थव्यवस्था) पर ध्यान देना चाहते हैं। इस जंग से निकलना चाहते हैं। अगर नेतन्याहू के कारण ईरान और लेबनान में युद्ध और भड़कता है, तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ेगी और अमेरिका एक अंतहीन जंग में फंस जाएगा, जो ट्रम्प को अपनी घरेलू राजनीति के लिए मंजूर नहीं है।

इजराइल और लेबनान के बीच में पहला सीज फायर 17 अप्रैल को हुआ था। 15 मई को इसे 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन सीजफायर के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। उसका तर्क है कि यह हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ सेल्फ डिफेंस है। इसलिए यह सीजफायर का उल्लंघन नहीं है। लेबनान की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 25 मई से 1 जून तक इजराइल के हमलों में करीब 250 लोग मारे गए। तो फिर ईरान ने अब बातचीत बंद करने की धमकी क्यों दी? वजह है इजराइल का 31 मई को लेबनान में इजराइली सेना का ऑपरेशन। इसमें इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जा कर लिया है। कासल यानी किला समझिए। इजराइली सेना ने एक वीडियो इस बारे में जारी किया जिसमें इस किले पर इजराइयली झंडा लहराता नजर आया। यह किला रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। यह दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी की घाटी के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और इजराइल की सरहद से 14.5 कि.मी. दूर है। यहां से पूरे इलाके पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इस किले का इतिहास करीब 900 साल पुराना है। इसे क्रुसेडर्स यानी धर्म युद्ध लड़ने वाले ईसाइयों ने बनवाया था। 44 साल पहले 1982 में इजराइल ने इसी किले पर पहली बार कब्जा जमाया था। तब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के लड़ाके इस किले पर काबिज थे। इजराइल ने पूरे 18 साल यानी 1982 से लेकर 2000 तक इस किले में अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाए रखी। अब 18 बरसों में हिजबुल्ला और दूसरे चरमपंथी इस किले पर लगातार गोरिल्ला हमले करते रहे। इजराइयली सैनिकों के लिए वहां ड्यूटी करना कभी भी आसान नहीं था। इस किले के नाम पर व्यूफोर्ट नाम की एक मशहूर फिल्म भी बनी थी जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। साल 2000 में जब इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई तो यह किला भी खाली कर दिया। 26 साल बाद इजराइली झंडा एक बार फिर इस किले पर लहराया गया। इस बात ने हिजबुल्ला और ईरान दोनों को बेचैन कर दिया।

आज का इतिहास

1883 ओरिएंट एक्सप्रेस, एक ट्रेन लाइन जो साज़िश और लक्जरी यात्रा के साथ बेगमेनिसम का संचालन करती है।
1888 अमेरिका के डेमोक्रेटर राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के लिए मनोनीत किये गये।
1899 फिलीपीन-अमेरिकी युद्ध के बीच एंटोनियो लूना की हत्या कर दी गई थी।
1915 डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया।
1928 हाउस और सीनेट चुनाव फिलीपींस में आयोजित किया गया, जिसमें नेसिअनलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की।
1941 दूसरा चीन-जापानी युद्ध-चूंगचींग पर पांच साल के अभियान में एक छंटनी के दौरान, 4,000 लोगों की मृत्यु श्वासनली व्हेन्थ सुरंग से हुई, जिसे वे अवरुद्ध हो गए थे।
1942 अमेरिका ने बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1963 युद्ध में ब्रिटिश राज्य सचिव जॉन प्रोफुमो ने एसेंशियल स्कैंडल में शामिल होने के बारे में पूछताछ के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्ती हुए और इस्तीफा दे दिया।
1967 इजरायल ने मिस्र पर हमला कर उसके करीब चार सौ लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए।
1968 फिलिस्तीनी आप्रवासी सिरहान सरहन ने अमेरिकी राजदूत होटल इनलोस एंजिल्स के किचन पेंट्री के अंदर अमेरिकी सीनेटररॉबर्ट एफ। कैनेडी को गोली मार दी - एक ऐसी घटना जिसने कई तरह के षड्यंत्रों को जन्म दिया है।
1969 एक अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलन मास्को में शुरू हुआ।
1972 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई।
1976 पूर्वी इदाहो, अमेरिका में टेटन डैम पहली बार भरे जाने वाले इसके जलाशय के रूप में ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्यारह लोगों की मौत हो गई और 13, 000 मवेशी मारे गए और 2 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ।
1981 रोग नियंत्रण केंद्र ने लॉस एंजिल्स में समलैंगिक पुरुषों में निमोसिस्टिस निमोनिया के मामलों का एक समूह दर्ज किया, जो एड्स के पहले दर्ज मामले थे।
1988 पहला राष्ट्रीय कैंसर उत्तरजीवी दिवस आयोजित किया गया।
1989 एक अनाम प्रदर्शनकारी, जिसे बाद में टैंक मैन करार दिया गया, तियानमेन स्क्वायरप्रिस्ट्स के दौरान एक तरफ खींचे जाने से पहले एकल-टैंकी ने चीनी टैंकों के एक स्तंभ को रोक दिया।

कांग्रेस का पुनरुत्थान : दक्षिण भारत दिखा रहा है राह

प्रो. प्रदीप माथुर

इतिहास मानो स्वयं को दोहरा रहा है। आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे, जनता पार्टी, से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। मात्र दो महीने पुरानी जनता पार्टी ने उत्तर, पश्चिम और पूर्व भारत में कांग्रेस जैसी पुरानी और स्थापित पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था। लेकिन दक्षिण भारत इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा और कांग्रेस के पुनरुत्थान का उत्प्रेरक बना। परिणामस्वरूप, सत्ता खोने के मात्र तीन वर्षों के भीतर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में लौट आई।

क्या अब एक बार फिर दक्षिण भारत कांग्रेस के पुनरुत्थान का उत्प्रेरक बनने जा रहा है और उसे नई दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा? निस्संदेह, इस बार परिस्थितियाँ काफी भिन्न हैं। अब लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि एक हानिकारक वैचारिक तंत्र के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसी क्षमता और करिश्मे वाला कोई नेता भी नहीं है। यह सच है कि मोदी सरकार जैसी मजबूत और जमी हुई सत्ता को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास इंदिरा गांधी के कद का नेता नहीं है। किंतु उसके पास अपार संभावनाओं वाले कई नेता हैं। इनमें नवीनतम नाम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलपति का है, जिनकी मात्र दो वर्ष पुरानी टीवीके पार्टी लगभग आधी सदी पुरानी सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल के तीव्र चुनावी संघर्ष और विदेश में खाड़ी युद्ध जैसी घटनाओं के बीच हम राष्ट्रीय राजनीति पर विजय थलपति की जीत के प्रभाव का सही आकलन नहीं कर पाए हैं। इसे किसी दूरस्थ दक्षिणी राज्य की एक छोटी घटना मानना बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें केवल एक लोकप्रिय फिल्म स्टार मानकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जिन्हें तमिलनाडु के फिल्म-प्रेमी लोगों ने उसी प्रकार सत्ता में पहुंचाया हो जैसा उन्होंने करुणानिधि, एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता के मामले में किया था।

विजय वैचारिक रूप से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो भारतीय लोकतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं, इससे पहले कि मोदी ने भारतीय राजनीति के संतुलन को बदलकर उसे हिंदुत्व और पूंजीपति-परस्त व्यवस्था की ओर मोड़ दिया। विजय खुलकर धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गरीब-समर्थक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, जो मोदी की भाजपा और उसके कॉर्पोरेट समर्थकों को

स्वीकार्य नहीं है। जब अनेक नेता बहुसंख्यक समुदाय के समर्थन के खोने के भय से धर्मनिरपेक्षता की बात करने से कतराते हैं, तब विजय ने ऐसी कोई झिझक नहीं दिखाई है। वे भारतीय धर्मनिरपेक्ष परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उभरे हैं—एक ईसाई, जो मात्र 6 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन जिन्हें 88 प्रतिशत हिंदू बहुसंख्यक समुदाय ने अपना नेता चुना है।

कांग्रेस की विचारधारा के प्रति विजय का समर्थन और राहुल गांधी के प्रति उनकी प्रशंसा किसी से छिपी नहीं है। जहाँ उत्तर भारत के भाजपा-विरोधी नेता, जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के प्रति सावधानीपूर्ण रुख अपनाते रहे हैं, वहीं विजय ने ऐसा कोई संकोच नहीं दिखाया। लगभग 50 वर्षों में पहली बार कांग्रेस तमिलनाडु की सत्तारूढ़ व्यवस्था का हिस्सा बनी है।

यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ अपने गठबंधन में पूरी तरह सहज नहीं हैं। उन्हें आशंका है कि मोदी की भाजपा से उनकी निकटता मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनके समर्थन को नुकसान पहुंचा सकती है, जो लंबे समय से उनके साथ रहे हैं। इसके अलावा, चंद्रबाबू नायडू महत्वाकांक्षी नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं।

कर्नाटक, तेलंगाना और केरल पहले से ही कांग्रेस के प्रभाव या नियंत्रण में हैं और तमिलनाडु में भी एक मित्रवत मुख्यमंत्री है। ऐसे में कांग्रेस का पुनरुत्थान धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से दक्षिण भारत से शुरू होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। निस्संदेह, इस बार संघर्ष अधिक कठिन है, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को केवल एक अत्यंत कुशल और चालाक नेता तथा उसकी पार्टी से ही नहीं, बल्कि सांप्रदायिक विचारधारा, विशाल धनबल, सरकारी मशीनरी के खुले उपयोग, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के हनन और एक अनुकूल मीडिया से भी मुकाबला करना पड़ रहा है।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियाँ हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बदल रही हैं। भाजपा भले ही चुनाव जीत रही हो, लेकिन वह लगातार जनसमर्थन खो रही है। अब जनता भी धर्म के नशे से धीरे-धीरे बाहर निकल रही है।

बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों को भाजपा और उसके वादों से निराश कर दिया है। जनरेशन-ज़ेड (त्द्दठु) विशेष रूप से नाराज़ है, जैसा कि नीट (हृश्वश्वञ्ज) परीक्षा-पत्र लीक प्रकरण पर उसकी तीखी प्रतिक्रिया और कॉकरोच जनता पार्टी को मिले व्यापक समर्थन से देखा जा सकता है।

चेन्नई में विजय थलपति का सत्ता में आना अकेले भाजपा जैसी मजबूत पार्टी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वे अकेले भी नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त प्रियंका गांधी भी हैं, जिनमें दक्षिण भारत के बहुत से लोग, विशेषकर महिलाएँ, अपनी प्रिय इंदिरा अम्मा की छवि देखती हैं। प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही केरल की वायनाड सीट जीतकर की है। यही दक्षिण भारत कभी इंदिरा गांधी के राजनीतिक पुनरुत्थान का भी आधार बना था, जब उन्हें कर्नाटक के चिकमंगलूर से संसद में भेजा गया था और उनकी राजनीतिक किस्मत फिर चमक उठी थी।

हालाँकि, विजय निश्चित रूप से एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने जा रहे हैं और भारतीय राजनीति में उनका आगमन लोकतांत्रिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगा। उनकी लोकप्रियता तमिलनाडु की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। भाजपा-विरोधी शक्तियों के साथ उनकी मौजूदगी स्पष्ट संकेत दे रही है कि सांप्रदायिक घृणा की राजनीति और पूंजीपति-परस्त व्यवस्था का दौर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और राजनीति अपने पुराने स्वरूप की ओर लौट सकती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे विशाल देश को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो उदारवादी हो, गरीबों के हितों की पक्षधर हो, निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाए, सार्वजनिक जीवन के स्थापित मानदंडों और मूल्यों का सम्मान करे, साहसिक विदेश नीति का पालन करे और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करे।

मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले जो स्थापित राजनीतिक संस्कृति प्रचलित थी, उसकी ओर लौटने में कितना समय लगेगा, यह कहना कठिन है। किंतु संकेत यही हैं कि यह प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं होगी।

कॉकरोच जनता पार्टी बनी युवाओं के राजनीतिक गुस्से का वायरल प्रतीक

देवांशु दत्ता

हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ऑनलाइन लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखी गई। इसके इंस्टाग्राम पेज, एक्स अकाउंट और वेबसाइट पर एक हफ्ते में 2.2 करोड़ से अधिक लोगों ने साइन-अप किया। फिर भारत में इसके सभी सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट को 'सुरक्षा कारणों' से ब्लॉक या बंद कर दिया गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इन प्रतिबंधों को कानूनी चुनौती दी है। लेकिन कॉकरोच(तिलचट्टों) का सफाया करना आसान नहीं है और इनके मीम लगातार फैलते जा रहे हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर कॉकरोच के मुखौटे और टी-शर्ट पहनकर जुलूस निकालते नजर आए। इस प्रचार की गति आश्चर्यजनक नहीं है। 'कॉकरोच' शब्द ने युवा, डिजिटल रूप से जागरूक राष्ट्र की नब्ज को छुआ है। 30 वर्ष से कम आयु के भारतीय चौबीसों घंटे स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं और यहां प्रति व्यक्ति डेटा खपत अन्य किसी भी देश से कहीं अधिक है। अधिकांश लोगों को कॉकरोच घिनौने लगते हैं। लेकिन अगर लक्षित समूह द्वारा इसे अपना लिया जाए तो अपमानजनक शब्दों को बेअसर किया जा सकता है। समाजशास्त्रियों ने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता, अश्वेत कार्यकर्ता और अन्य लक्षित समूहों ने ऐसा अक्सर किया है। दिपके ने व्यंग्यात्मक रूप से कॉकरोच वाले अपमानजनक शब्द को अपना लिया। लाखों युवाओं ने उनका अनुसरण किया। किसी संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह 'आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज' है। इस मीम को जन्म देने वाले मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि उनका इशारा फर्जी डिग्रियों वाले लोगों की तरफ था। यह पता लगाना वास्तव में असंभव है कि युवा भारतीय आलसी हैं या नहीं, क्योंकि उनमें से एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है, और बेरोजगारों को यह साबित करने का अवसर नहीं मिलता कि वे मेहनती हो सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की इस लहर का एक मुख्य कारण युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर है। 35 वर्ष से कम आयु के भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है और कुछ तो एक दशक से भी अधिक समय से नौकरी की तलाश में हैं। अन्य लोग जो भी काम मिल पाता है, उसे कर रहे हैं। अत्यधिक योग्यता प्राप्त लोगों सहित लाखों युवा, किसी भी विज्ञापित नौकरी के लिए हताशा में आवेदन करते हैं। कोई भी सरकार इस मोर्चे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के कार्यबल में प्रवेश करने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। फर्जी डिग्रियों के मामले में, 2026 एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। नीट अंडरग्रेजुएट परीक्षा के पेपर लीक होने और सीबीएसई वेबसाइट विवाद को देखते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि समकालीन भारतीय डिग्रियों और प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता संदिग्ध जरूर है। यह युवाओं के गुस्से का एक और कारण है। सीजेपी की वेबसाइट पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली एक याचिका थी। वेबसाइट बंद होने से पहले ही इस पर 6 लाख हस्ताक्षर हो चुके थे। नीट परीक्षा घपला और सीबीएसई की वेबसाइट को आसानी से हैक करके अंक बदलने की बात सामने आने के बाद परीक्षा परिणामों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ी का सीधा असर उस आयु वर्ग के सभी लोगों पर पड़ता है। उन लड़कों और लड़कियों को अपनी डिग्रियों की विश्वसनीयता साबित करनी होगी, भले ही उन्हें अच्छे अंक मिले हों। बेरोजगारी और संदिग्ध रूप से संचालित परीक्षाओं का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ता है। लेकिन सीजेपी के 'कॉकरोच' ने महंगाई की मार और इससे उनके परिवारों पर पड़ने वाले कष्टों को भी उजागर किया है।

तृणमूल कांग्रेस में बगावत की दस्तक

कांतिलाल मांडोत

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय ऐसा था जब ममता बनर्जी का नाम ही तृणमूल कांग्रेस की पहचान माना जाता था। वर्ष 2011 में वामपंथी शासन को समाप्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने स्वयं को बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन समय के साथ जिस राजनीतिक शैली ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, वही शैली अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरती असंतोष की आवाजें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। विधायकों की अलग बैठकें, नेतृत्व पर सवाल और पार्टी में टूट की चर्चाएं इस संकट को और गहरा कर रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे वर्षों से चल रही ऐसी नीतियां और कार्यशैली रही हैं जिनसे पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर असंतोष बढ़ता गया। तुष्टिकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी संस्कृति, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों ने धीरे-धीरे जनता के बीच टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी हार उसी असंतोष की अभिव्यक्ति मानी जा रही है।

ममता बनर्जी ने लंबे समय तक खुद को अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं जिनका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिला, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि राज्य में विकास और सुशासन की बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी गई। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संतुलन बनाने के बजाय विशेष वर्गों को खुश करने की कोशिश ने सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इसका प्रभाव धीरे-धीरे चुनावी राजनीति पर भी दिखाई देने लगा।

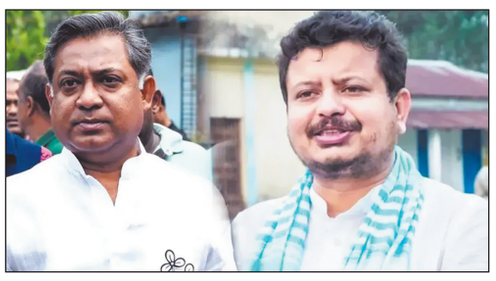

बंगाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी रहीं। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक हिंसा, धमकी और बूथ कब्जाने के आरोप लगते रहे। विपक्षी दलों का आरोप रहा कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। यही कारण है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल

उठते रहे। जनता के एक बड़े वर्ग में यह धारणा बनी कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जबकि आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कट मनी का मुद्दा भी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी हार के बाद कई क्षेत्रों में नेताओं द्वारा लोगों को पैसे लौटाने की खबरें सामने आना इस बात का संकेत माना गया कि जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरा आक्रोश था। जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता जनता के विश्वास को खोने लगते हैं तो उसका असर अंततः चुनावी नतीजों में दिखाई देता है।

आज टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं बल्कि आंतरिक असंतोष भी है। पार्टी के कई नेता और विधायक महसूस कर रहे हैं कि संगठन में संवाद की कमी है और निर्णय कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं। यही कारण है कि चुनावी हार के तुरंत बाद अलग बैठकों और बागी तेवरों की खबरें सामने आने लगीं। यदि किसी दल के विधायक सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाने लगें तो यह केवल चुनावी पराजय का परिणाम नहीं बल्कि लंबे समय से पनप रहे असंतोष का संकेत होता है।

ममता बनर्जी की राजनीति लंबे समय तक उनके व्यक्तिगत करिश्मे पर आधारित रही। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में केवल व्यक्तित्व के आधार पर पार्टी को एकजुट रखना कठिन होता जा रहा है। नई पीढ़ी के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वे संगठन में अधिक भागीदारी चाहते हैं। यदि उन्हें अवसर नहीं मिलता तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। वर्तमान संकट इसी स्थिति की ओर इशारा करता है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बंगाल की जनता अब केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट नहीं है। वह बेहतर प्रशासन, रोजगार, निवेश और सुरक्षा की अपेक्षा रखती है। राज्य से उद्योगों का पलायन, बेरोजगारी और निवेश की कमी जैसे मुद्दों ने भी जनता के भीतर निराशा पैदा की है। जब विकास के वादों की तुलना जमीनी वास्तविकताओं से होती है तो सरकार की जवाबदेही तय होती है। यही कारण है कि चुनाव में मतदाताओं ने सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी दिखाई।

टीएमसी के भीतर उभर रहा संकट यह भी दर्शाता है कि चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व अभी तक स्पष्ट दिशा देने में सफल नहीं हुआ है। यदि विधायक और वरिष्ठ नेता अलग-अलग समूहों में बैठकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं तो यह संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है। ऐसी स्थिति में नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संवाद स्थापित करना और विश्वास बहाल करना होती है। लेकिन यदि असंतोष को केवल विरोधियों की साजिश बताकर खारिज किया जाता है तो समस्या और गंभीर हो सकती है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने एक मजबूत जननेता के रूप में लंबा सफर तय किया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां उनके लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकती हैं। जनता का विश्वास बनाए रखना और पार्टी को एकजुट रखना दोनों ही बड़ी चुनौतियां हैं। तुष्टिकरण की राजनीति और कथित जंगलराज के आरोपों ने जिस तरह जनता के बीच असंतोष पैदा किया, उसका असर चुनावी परिणामों में दिखाई दिया है। अब वही असंतोष पार्टी के भीतर भी स्वर लेने लगा है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तृणमूल कांग्रेस इस संकट से कैसे निपटती है। यदि पार्टी आत्ममंथन कर अपनी कार्यशैली में बदलाव लाती है तो स्थिति संभल सकती है, लेकिन यदि जनता के संदेश और संगठन के भीतर उठ रही आवाजों को नजरअंदाज किया गया तो यह संकट और गहरा सकता है। बंगाल की राजनीति फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चुनावी हार केवल सीटों की हार नहीं बल्कि एक राजनीतिक मॉडल पर उठे गंभीर प्रश्नों का संकेत भी है। यही कारण है कि टीएमसी में उभरती बगावत को केवल आंतरिक कलह नहीं बल्कि वर्षों से जमा होते जन असंतोष के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है।

टीएमसी और डीएमके के बुरे हश्र से विपक्षी एकता पड़ी कमजोर

नीरज कुमार दुबे

केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए पिछले कुछ समय से संसद के भीतर और बाहर विपक्ष की एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही थी। विशेषकर महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में सरकार को झटका मिलने के बाद यह माना जा रहा था कि विपक्षी दल मिलकर सरकार के महत्वाकांक्षी विधायी कार्यक्रम को रोक सकते हैं। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों तृणमूल कांग्रेस और द्रविड मुनेत्र कषगम के भीतर पैदा हुए संकट ने सत्ता पक्ष को नई मजबूती देने के संकेत दिए हैं।

पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस अपने गठन के बाद के सबसे गंभीर संकट से गुजर रही है। पार्टी के भीतर पहली बार खुला विभाजन सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के कुल अस्सी विधायकों में से 58 विधायकों के एक बड़े समूह ने ममता बनर्जी की पसंद के खिलाफ जाकर ऋत्ब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया। वर्ष 1998 में स्थापित पार्टी में यह पहला बड़ा विभाजन माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह असंतोष केवल नेतृत्व शैली तक सीमित नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी नाराजगी गहराती जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी अपने सांसदों को एकजुट रख पाएगी या फिर बंगाल में विधायकों की तरह दिल्ली में सांसदों में भी टूट देखने को मिल सकती है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदरखाने चिंता गहरी

बताई जा रही है। एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि इस समय पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती संसद और उसके बाहर अपने सांसदों को एकजुट बनाए रखना है।

इस बीच विपक्षी दलों के गठबंधन के भीतर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। लोकसभा में सरकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक को रोकने में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड मुनेत्र कषगम की साझा रणनीति निर्णायक रही थी। इन दलों के कुल 185 सांसदों ने सदन की एक तिहाई से अधिक संख्या जुटाकर सरकार की राह रोकी थी। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर संकट और तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक समीकरणों ने विपक्षी एकता को कमजोर कर दिया है।

तमिलनाडु में द्रविड मुनेत्र कषगम और कांग्रेस के संबंधों में भी खटास आ गयी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने द्रविड मुनेत्र कषगम से दूरी बनाते हुए विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्रि कषगम सरकार के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद द्रविड मुनेत्र कषगम के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। अब उसकी सीधी टक्कर तमिलगा वेत्रि कषगम से मानी जा रही है, जो कांग्रेस की सहयोगी है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह आकलन किया जा रहा है कि ऐसे हालात में द्रविड मुनेत्र कषगम केंद्र सरकार के प्रति अपनी पुरानी आक्रामक नीति में नरमी ला सकता है और अधिक व्यवहारिक रुख अपना सकता है।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के संकट ने राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। आठ जून को लंबे अंतराल के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल होकर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि द्रविड मुनेत्र कषगम ने अब तक बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है, जिससे विपक्षी एकता को लेकर और सवाल खड़े हो गए हैं।

उधर, तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी उथलपुथल के बीच पार्टी नेतृत्व लगातार बैठकों में जुटा हुआ है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हालात पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करने के लिए लंबी बैठकें की हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चिंता संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर है, जहां विपक्ष की भूमिका पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही। अब तृणमूल कांग्रेस को संसद में अपनी रणनीति और जनसंपर्क दोनों को नए सिरे से तय करना होगा।

देखा जाये तो विपक्षी दलों की कमजोर होती एकजुटता और हाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति ने केंद्र सरकार का आत्मविश्वास बढ़ाया है। सरकार अब एक साथ चुनाव कराने जैसे महत्वाकांक्षी विधायी कार्यक्रमों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में है। साथ ही विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारों का राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के कुछ विपक्षी सांसदों के पाला बदलने की चर्चाओं ने भी इन अटकलों को और बल दिया है।

बहरहाल, राजनीतिक हलकों में अब यह माना जा रहा है कि यदि विपक्ष अपने आंतरिक मतभेदों को जल्द दूर नहीं कर पाया तो संसद में सरकार को घेरने की उसकी क्षमता कमजोर पड़ सकती है। आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस और द्रविड मुनेत्र कषगम की दिशा ही यह तय करेगी कि विपक्ष दोबारा मजबूत एकजुटता कायम कर पाता है या भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजनीति की राह और आसान हो जाती है।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अहम संदेश

देवेश त्रिपाठी

ऐसे समय में, जब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दल लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय का इसे पूरी तरह से वैध और संविधानसम्मत ठहराने वाला निर्णय चुनाव-प्रक्रिया की शुचिता और निर्वाचन आयोग के अधिकारों के पक्ष में एक अहम संदेश देता है। इससे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और पंजाब समेत सोलह राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के सत्यापन की आसन्न प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग के अधिकारों की पुष्टि ही हुई है। हालांकि, यह शर्त भी महत्वपूर्ण है कि आयोग को प्रत्येक राज्य में इस प्रक्रिया को दोहराने का औचित्य स्पष्ट करना होगा। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज करते हुए कि एसआईआर घुसपैठियों को हटाने के नाम पर पिछले दरवाजे से नागरिकता की ही जांच है, साफ कर दिया है कि यह पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। हालांकि, अदालत के फैसले का यह पहलू भी विचारणीय है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता संबंधी पहलुओं की जांच कर सकता है, पर इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम नहीं होगा। दरअसल, इससे तो किसी को इन्कार नहीं होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की शुद्धता निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है। अगर सूची में मृत, स्थानांतरित हो चुके या अपात्र लोगों के नाम बने रहते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठेंगे। ऐसे में, एसआईआर की वैधता पर

मुहर लगाने वाला अदालती फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लंबे समय से खिंचे आ रहे मुद्दे के संदर्भ में एक किस्म की स्पष्टता लेकर आया है। पर, इसके साथ ही चुनाव आयोग का यह कर्तव्य भी है कि किसी पात्र मतदाता को मताधिकार से वंचित न होना पड़े। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश के अनेक हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, खासकर प्रवासी मजदूर, गरीब या बुजुर्ग नागरिक, जो ऐसे सत्यापन अभियानों में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए, शीर्ष न्यायालय के निर्णय को चुनाव आयोग की शक्तियों की पुष्टि के साथ उसके दायित्वों की पुनर्पुष्टि के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद एसआईआर से जुड़े विवाद खत्म होंगे और राजनीतिक दल भी केवल चुनावी चश्मे से देखने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के व्यापक संदर्भ में इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

दुर्गा एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है सबसे शक्तिशाली

मां दुर्गा, की आराधना का पर्व नवरात्र इन दिनों भारतवर्ष में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इन नौ दिनों में शक्ति की आराधना, भक्ति से करने पर मां के भक्तों को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के बाद दशहरा आता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा, भगवान श्रीराम द्वारा लंकापति रावण की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं।

मां दुर्गा का स्वरूप तीनों लोकों में अलौकिक है। दुर्गा रूप में मां सकारात्मक ऊर्जा वायुमंडल में प्रवाहित करती हैं। वह शक्ति (नारी शक्ति/ ऊर्जा) का प्रतीक हैं। मां दुर्गा ने इस पृथ्वी से नकारात्मक ऊर्जा यानी दानवों का संहार किया। मां दुर्गा को आदि शक्ति कहा जाता है, त्रिदेवियां (देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती) भी मां आदिशक्ति का ही रूप हैं। मान्यता है कि जब मां दुर्गा महिषासुर जैसे भयानक दानव से युद्ध करने जा रही थीं, तब त्रिदेवों के साथ देवताओं ने भी उन्हें अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए थे।

ये सभी शस्त्र अपने आप में दुर्लभ थे। तब मां ने इन्हीं शस्त्रों की सहायता से इस दैत्य का संहार किया। दरअसल दुर्गा, एक संस्कृत शब्द है। जिसका अर्थ होता है सबसे शक्तिशाली। इसलिए मां दुर्गा सभी देवी-देवताओं में शक्तिशाली और शक्ति की देवी मानी गई हैं। मां दुर्गा का नाम मात्र लेने से नकारात्मक शक्तिया और दोष- अहंकार, ईर्ष्या, पूर्वाग्रह, घृणा, क्रोध, लालच और स्वार्थ भाग जाते हैं।

वेबसाइट इंडिया करंट्स में सत्या कालरा लिखते हैं, 'मां दुर्गा के आठ हाथ हैं जिनमें आठ तरह तरह के शस्त्र हैं। हर शस्त्र और हाथों की मुद्राएं जिंदगी के लिए कुछ न कुछ सीख देतीं है।' दुर्गा के ऊपरी और दाएं हाथ में चक्र है। यह धर्म चक्र है। यह हमें अपने कर्तव्य और जिंदगी की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा करने की सीख देता है। मां दुर्गा के ऊपरी बाएं हाथ में शंख है। यह चिन्ह कहता है कि हमें संतोष के साथ खुशी और हंसमुख रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

मां दुर्गा की तलवार उन्मूलन का प्रतीक है। हमें भेदभाव और हमारे बुरे गुणों दूर करना चाहिए। निचले हाथ में मां दुर्गा धनुष और तीर लिए हैं। यह चिन्ह हमें सीख देता है कि भगवान राम की तरह हमारा चरित्र होना चाहिए। जीवन कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पडता है लेकिन हमें अपना धैर्य और चरित्र(मान-सम्मान) नहीं खोना चाहिए। मां दुर्गा के हाथ में कमल का होना प्रतीक है कि हम बाहरी दुनिया में मोह-माया रहित होकर जीवन जीना चाहिए। जैसे कमल, दलदल में खिलकर भी मुस्कुराता है। ठीक उसी तरह इस दलदल रूपी और त म ा म विकारों से भरे संसार में अपनी मुस्कान नहीं खोना चाहिए। मां दुर्गा के हाथ में गदा, हनुमान जी जैसी शक्ति का प्रतीक है। हनुमानजी भक्ति और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में भक्ति और समर्पण का भाव रखना चाहिए। भक्ति और सर्वशक्तिमान की इच्छा के रूप में परिणाम स्वीकार करते हैं। मां दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल साहस का प्रतीक है। त्रिशूल सीख देता है कि हम हमारे नकारात्मक गुणों का संहार कर जीवन में चुनौतियों का सामना करें। सफलता हमारे कदमों में होगी। मां दुर्गा के एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। इसका अर्थ है हमें अपनी और दूसरों की गलतियों को माफ कर जिंदगी में आगे बड जाना चाहिए। मां दुर्गा को शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है। वह इसलिए कि मां शक्ति हैं। और बाघ/ शेर असीमित शक्ति का प्रतीक है। वह जंगल का राजा है। यानि शक्ति सिर्फअसमित शक्ति के सानिध्य में ही रह सकती हैं। शेर के पर भी मां दुर्गा को बैठे हुए प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता है। शेर दरअसल क्रोध, अहंकार, स्वार्थ के रूप में अनियंत्रित पाशविक प्रवृत्तियों को नष्ट करने का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी अच्छाईयों को नियंत्रित कर नकारात्मक शक्तियों(लालच, ईर्ष्या, इच्छा, आदि अन्य) का संहार करें। मां दुर्गा अमूमन लाल साडी पहनती हैं। लाल रंग लाल कार्रवाई का प्रतीक है और लाल कपडे बुराई को नष्ट करने के प्रतीक हैं। मानव जाति की रक्षा और उन्हें दानवों से बचाने के लिए मां हमेशा तत्पर रहती हैं। मां के पास सकारात्मक ऊर्जा का स्त्रोत है, जिससे वह नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। मां दुर्गा स्त्री में शक्ति का प्रतीक हैं। वह रचनात्मकता की मूर्ति हैं। उनके चेहरे की आभा से निकलता शुद्ध प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मां की आराधना और उपासना जो भी भक्त करता है। वह अपने जीवन में हमेशा विजयश्री हासिल करता है।

भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे

हमारे वेदों में चार युगों का वर्णन मिलता है। ब्रहमाजी का एक दिन यानी चार वेदों का समय है। यह समय सौर वर्ष (12 माह से सौर वर्ष बनता है और सौर वर्ष का प्रथम दिन 'मेष' होता है।) में उल्लेखित है। चार युगों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग आते हैं। त्रेतायुग दूसरा युग था जिसमें अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु तीन अवतार लिए थे, जो क्रमश: वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्रीराम अवतार के नाम से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हैं।

त्रेतायुग में भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में वामन अवतार लिया गया था। पहले चार अवतार क्रमश: मत्स्य, कच्छप, वाराह और नृसिंह थे। वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से तीन पग जमीन मांग कर धरती की रक्षा की थी। छठवां अवतार भगवान ने परशुराम का लिया। इसके बाद भगवान श्रीराम के रूप में भगवान विष्णु इस धरती पर जन्मे थे।

वामन अवतार: भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता अदिति थीं। वह बौने ब्राहमण के रूप में जन्मे थे। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक में पुन: अधिकार स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। दरअसल देवलोक पर असुर राजा बली ने विजयश्री हासिल कर इसे अपने अधिकार में ले लिया था। राजा बली विरोचन के पुत्र और प्रहाद के पौत्र थे। उन्होने अपने तप और पराक्रम के बल पर देवलोक पर विजयश्री हासिल की थी। राजा बलि महादानी राजा थे, उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। यह बात जब वामन भगवान को पता चली तो वह एक बौने ब्राहमण के वेष में बली के पास गये और उनसे अपने रहने के लिए तीन पग के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकडी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने के बावजूद बली ने वामन को वचन दे डाला। इस तरह भगवान ने दो पग में धरती, आकाश नाम लिया, चौथा पग उन्होंने राजा बलि के सिर पर रखा था। जिसके बाद से राजा बलि को मोक्ष प्राप्त हुआ।

परशुराम अवतार: भगवान विष्ण के छठवें अवतार के रूप में राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्में थे। इस अवतार में वह भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु(फरसा) प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किन्तु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किये रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे।

श्रीराम अवतार: श्रीहरि ने सातवें अवतार के रूप में श्रीराम के नाम से जन्म लिया। वह अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्मे थे। इस अवतार में वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने लंकापति रावण के अलाव कई दैत्यों का अंत किया। श्रीराम की संपूर्ण गाथा वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित है।

कृष्ण के गीता के उपदेश अर्जुन के अलावा विश्व में चार और लोग सुन रहे थे

पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ (अर्जुन) को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे उस समय धनुर्धारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में चार और लोग सुन रहे थे जिसमें पवन पुत्र हनुमान, महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित सदस्य संजय और बर्बरीक शामिल थे। आपको बताते चलें बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र तथा भीम के पोते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि कौरवों और पाण्डवों के इस भयंकर युद्ध को देख सकते हैं। जब गीता का उपदेश चल रहा उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे जबकि संजय, धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी वह वही थी जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण की मंशा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्त्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में वो भारत को आने वाले विनाश से बचा लें। यही नहीं यही वह चार व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को विश्वरूप के रूप में देखा। दसवें अध्याय के सातवें श्लोक तक भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी विभूति, योगशक्ति तथा उसे जानने के माहात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर ग्यारहवें श्लोक तक भक्तियोग तथा उसका फल बताया। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों तथा योगशक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योगशक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रहमांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुइ तब ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ में भगवान श्रीकृष्ण ने विश्वरूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया। इसी विराट स्वरूप में समस्त ब्रहमांड को समाहित देख अर्जुन मोह मुक्त हुए तथा युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त की।

कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इन विशेष मुहूर्त का ध्यान रख सकते हैं

कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम भारतीय मुहूर्त जरूर देखते हैं। मुहूर्त देखने का चलन सदियों से चला आ रहा है। यदि आप स्वयं का व्यवसायिक, औद्योगिक या फिर किसी भी तरह की मशीन को स्थापित करना चाहते हैं तो इन विशेष मुहूर्त का ध्यान रख सकते हैं। औद्योगिक मुहूर्त कुटीर, लघु और भारी उद्योगों के शुभारंभ के लिए अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा नक्षत्र शुभ माने गए हैं। मशीन स्थापना मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग और रवि योग में मशीन स्थापना शुभ होता है। इसके अलावा व्यक्ति की चंद्र राशि व गोचर के चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए लग्न शुद्धि पर विचार करना चाहिए।

व्यवसायिक मुहूर्त मुहूर्त के मूलभूत सिद्धांत वहीं रहते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। मुहूर्त लग्न में चंद्रमा 6,8,12 में नहीं होना चाहिए। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो कोई भी शुभ कार्य करते समय शुभ राशि से गोचर का चंद्रमा 4,8,12 में नहीं होना चाहिए। चैत्र और पौष माह में कार्य वर्जित माने गए हैं। इसलिए वर्जित योगों व भद्रा आदि में कोई शुभ कार्य आरंभ न करें। रिक्ता तिथि यानी 4,9,14 में शुभारंभ नहीं करना चाहिए। मंगलवार और बुधवार छोडकर सभी वार शुभ रहते हैं। लोहा, कोयला और ज्योतिष कार्य शनिवार को भी किया जा सकता है। नई दुकान, शोरूम व कार्यालय खोलने के लिए अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद व रेवती नक्षत्र शुभ हैं।

शिवलिंग की पूजा करने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे शिवजी अति प्रसन्न होते हैं

शिव, महादेव, भोले शंकर या फिर नीलकंठ। भगवान शिव को न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो विनाश के देवता है यानि सृष्टि में जब-जब पाप की अधिकता हो जाती है तो शिव प्रलय लीला द्वारा पुन: संसार का सृजन करते हैं। वहीं भगवान शिव की पसंद की बात करें तो उनकी पसंद अन्य देवताओं से काफी अलग है।

भगवान शिव के एक अन्य रूप 'शिवलिंग' भी कई मायनों में अलग है।शिवलिंग की पूजा करने में कुछ ऐसे रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है जो भगवान शिव को बहुत पसंद है। शिवलिंग को दूध से स्नान करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को दूध से अभिषेक किया जाना बेहद पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग को दूध से स्नान क्यों करवाया जाता है। वास्तव में इसके पीछे भी एक कहानी है।

समुद्र मंथन की पूरी कथा विष्णुपुराण और भागवतपुराण में वर्णित है। जिसमें एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष की उत्पत्ति हुई थी तो पूरा संसार इसके तीव्र प्रभाव में आ गया था। जिस कारण सभी लोग भगवान शिव की शरण में आ गए क्योंकि विष की तीव्रता को सहने की ताकत केवल भगवान शिव के पास थी। शिव ने बिना किसी भय के संसार के कल्याण हेतु विष पान कर लिया। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। विष का घातक प्रभाव शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी गंगा पर पडने लगा। ऐसे में शिव को शांत करने के जल की शीलता भी काफी नहीं थी। सभी देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने का निवेदन किया। लेकिन अपने जीव मात्र की चिंता के स्वभाव के कारण भगवान शिव ने दूध से उनके द्वारा ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। स्वभाव से शीतल और निर्मल दूध ने शिव के इस विनम्र निवेदन को तत्काल ही स्वीकार कर लिया। शिव ने दूध को ग्रहण किया जिससे उनकी तीव्रता काफी सीमा तक कम हो गई परंतु उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा।

कठिन समय में बिना अपनी चिंता किए दूध ने शिव और संसार की सहायता के लिए दूध ने शिव के पेट में जाकर विष की तीव्रता को सहन किया। इसलिए शिव को दूध अत्यधिक प्रिय है। वहीं दूसरी तरफ शिव को सांप भी बहुत प्रिय है क्योंकि सांपों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए विष की तीव्रता स्वंय में समाहित कर ली थी।इसलिए अधिकतर सांप बहुत जहरीले होते हैं।

मन का संदेह

एक व्यक्ति की घडी खो गई। उसने पूरे घर में खोज लिया, पर वह कहीं नहीं मिली। अचानक उसकी नजर खिडकी के पार घर के बगीचे में काम करने वाले लडके पर गई। उसे वह कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। संदेह आंखों में भरकर जब उस व्यक्ति ने लडके की ओर देखा, तो उसने नजरें झुका लीं। उस व्यक्ति को यकीन हो गया कि घडी उसी ने चुराई है। वह लडके पर नजर रखने लगा। उसे लडके की हर गतिविधि से लग रहा था कि वही चोर है। वह व्यक्ति लडके से कडाई से पूछताछ करने की बात सोच ही रहा था कि एक दिन कबर्ड की सफाई करते हुए उसे वह घडी मिल गई। उसे याद आया कि उसने ही एक दिन अपने कपडों के साथ अपनी घडी कबर्ड में रखी थी। लडका अब भी बगीचे में काम कर रहा था।

व्यक्ति ने खिडकी से लडके की ओर फिर देखा। लडके ने उसे इस तरह देखकर नजरें नीची कर लीं, लेकिन अब उस व्यक्ति को लडके की कोई गतिविधि संदिग्ध नहीं लग रही थी। कथा मर्म : संदेह हमारे मन पर कब्जा जमाकर हमें गलत फैसले लेने के लिए बाध्य कर देते है।

महाभारत के बाद कैसे खत्म हुआ श्रीकृष्ण सहित पूरा यदुवंश

अठारह दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पाँचों पांडवों को छोडकर पांडव कुल के अधिकाँश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण, युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया वो था 'श्री कृष्ण जी का यदुवंश'।

गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप : महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठर का राजतिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्रीकृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया की जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्रीकृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गये थे।

यदुवंशी अपने साथ अन्न-भंडार भी ले आये थे। कृष्ण ने ब्राहमणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत-युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकि और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकि ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भडक उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक-दूसरे का संहार करने लगे।

इस लडाई में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकि समेत सभी यदुवंशी मारे गये थे, केवल बब्रु और दारूक ही बचे रह गये थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलरामजी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए।

बहेलिये का तीर लगने से हुई श्रीकृष्ण की मृत्यु बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्रीकृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था।

जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्रीकृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिए ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड दिया जो कि श्रीकृष्ण के तलवे में जाकर लगा।

जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्रीकृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमायाचना करने लगा। तब श्रीकृष्ण ने बहेलिए से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है।

अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिए के जाने के बाद वहां श्रीकृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्रीकृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अत: सभी लोग द्वारिका छोड दो, क्योंकि यह नगरी अब जल मग्न होने वाली है।

मेरी माता, पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और

उन्होंने श्रीकृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्रीकृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद भागवत के अनुसार जब श्रीकृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए।

देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलरामजी की पत्नियां, श्रीकृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिण्डदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए।

इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्रीकृष्ण के निवास स्थान को छोडकर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्रीकृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पाण्डवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी।

इसी यात्रा में ही एक-एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। वानर राज बाली ही था जरा बहेलिया संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी, जैसी बाली को दी थी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों को लेकर केंद्र पर बरसे खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर विफल रही है और अपनी नाकामियों को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों को छिपा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खरगे ने कहा कि NFHS-6 के आंकड़ों ने भाजपा सरकार की पूर्ण अक्षमता को उजागर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश में हर पांच में से एक बच्चा गंभीर कुपोषण का शिकार है, जबकि एक-तिहाई बच्चे कम वजन के हैं। इसके अलावा 6 से 23 महीने की उम्र के 84 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। खरगे ने NFHS-5 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और हर पांच में से एक महिला कुपोषित है।

राहुल गांधी ने अल्मोड़ा से फोन पर किया शंखनाद

देहरादून। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता

विपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अपनी निर्धारित यात्रा पूरी नहीं कर सके। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में ही फंस गया, इसके बाद उन्हें पंतनगर हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। हालांकि, राहुल गांधी ने हार नहीं मानी और एक फोन कॉल के माध्यम से परिवर्तन का शंखनाद वाली जनसभा को संबोधित किया।इसके पहले अपने एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अपने प्यारे भाइयों और बहनों से न मिल पाने पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वे लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनना, उनके सुख-दुख, आशाओं और चिंताओं को समझना चाहते थे, लेकिन मौसम की गंभीर खराबी ने इस बात को असंभव बना दिया। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे सुबह पंतनगर पहुंच गए थे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर पायलट ने अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरने से साफ इंकार किया।

कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज

नई दिल्ली। पंजाब में 2027 विधानसभा

चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के दावे ने अटकलों को बल दिया है, जिसके अनुसार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि कैप्टन उनके संपर्क में हैं और उन्हें अपना वरिष्ठ साथी बताया, जिससे उनकी वापसी की संभावनाएं बढ़ी हैं। गौरतलब है कि कैप्टन और हुड्डा की दोस्ती पुरानी है, इसके बाद हो सकता है कि हुड्डा ही कैप्टन की कांग्रेस में वापसी के वाहक बनें।हालांकि, पंजाब भाजपा के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने दावे को खास तवज्जो न देकर कहा कि केवल संपर्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, तब खुद कहती हैं कि हुड्डा किसी के संपर्क में नहीं रहते, इसलिए इस बात के कोई और मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।

एनआईए की पश्चिम बंगाल के 9 स्थानों पर छापेमारी

कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

ने पश्चिम बंगाल के भांगर विस्फोट मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में 9 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी इस मामले की गहन जांच कर रही है, जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित पहलुओं को देखते हुए अपने हाथ में लिया है।

जानकारी के अनुसार, एनआईए ने 26 अप्रैल 2026 को इस मामले की जांच औपचारिक रूप से संभाली थी। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर क्षेत्र में छापेमारी कर 79 देसी बम, विस्फोटक सामग्री तथा बम निर्माण में उपयोग होने वाले अन्य सामान बरामद किए थे। इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं। मामले की शुरुआत 25 अप्रैल को उत्तर काशीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी से हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में बड़ी मात्रा में देसी बम और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी गई है।

शिवकुमार ने बीके हरिप्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने

गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। एक्स पर एक पोस्ट में शिवकुमार ने लिखा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बीके हरिप्रसाद की नियुक्ति पर हार्दिक बधाई। उनके व्यापक राजनीतिक अनुभव और संगठन की गहरी समझ के साथ, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस और भी मजबूत और एकजुट होगी। मैं उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में सफलता की कामना करता हूं और आने वाले वर्षों में पार्टी द्वारा नई ऊंचाइयों को छूने की आशा करता हूं। हरिप्रसाद को आगामी राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भी नामित किया गया है। इस निर्णय की घोषणा करते हुए एआईसीसी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बी के हरिप्रसाद को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी चेतावनी को भाजपा ने नकारा

अमित मालवीय ने गिनाई मोदी सरकार की आर्थिक उपलब्धियां

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस दावे का खंडन किया कि सरकार द्वारा देश को अंतरराष्ट्रीय संकट से बचाने वाले उपायों को हटाने के कारण भारत को आर्थिक सुनामी का सामना करना पड़ रहा है। मालविया ने राहुल गांधी पर भय फैलाने का आरोप लगाया और पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक तनावों के बीच भारत की मजबूती के प्रमाण के रूप में विभिन्न आर्थिक संकेतकों का हवाला दिया।

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने मई 2026 में ई-वे बिल जनरेशन में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की निरंतर गतिविधियों का उल्लेख किया, जिसमें क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) क्रमश: 56.6 और 58.9 रहा। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य 3.48 प्रतिशत से नीचे रही और वित्त वर्ष 2026 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह रिकॉर्ड 94.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत सेवा निर्यात से बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को

समर्थन मिल रहा है। मालवीय ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था में झटकों को झेलने की क्षमता की कमी के संकेत नहीं हैं। ये लचीलेपन के संकेत हैं। सरकार ने नागरिकों, व्यवसायों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए सीधे उपाय भी किए हैं। मालवीय ने अंतरराष्ट्रीय संकट से जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया, जिनमें कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती, आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं।

उन्होंने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 का उल्लेख किया, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है, जबकि गैर-एमएसएमई और एयरलाइंस को 90% कवरेज मिलता है। पात्र उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक अतिरिक्त ऋण सहायता उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए है।

आर्थिक स्थिति पर सरकार घबराहट में, अध्यादेश सिर्फ दिखावा : जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 जून को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मोदी सरकार पर मौजूदा आर्थिक स्थिति के कारण घबराहट की स्थिति में होने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि मोदी सरकार स्पष्ट रूप से घबराहट की स्थिति में है और मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर अपने ही तंत्र के

भीतर से ही घिरी हुई है। उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित एक समाचार का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले 12.5% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि सत्ताधारी दल से जुड़े एक टीवी चैनल के समाचार के अनुसार, मोदी सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है, जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले 12.5% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। यह दर जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में निर्धारित की गई थी। उन्होंने प्रस्तावित उपाय को एक अस्थायी समाधान बताया जो अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करने में विफल है। रमेश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिकॉर्ड तोड़ कॉर्पोरेट आय के बावजूद भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश कमज़ोर बना हुआ है, और बताया कि जीडीपी के अनुपात में निवेश में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि असली समस्या यह है कि भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश बहुत सुस्त है। जो लोग भारत में निवेश कर सकते हैं और जिन्हें करना ही चाहिए, वे या तो विदेशों में निवेश कर रहे हैं या घरेलू निवेश को टाल रहे हैं। कॉर्पोरेट आय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी कॉर्पोरेट निवेश की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

टीएमसी में फूट के बीच बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन

संदीपन साहा के खिलाफ मार्च निकाला

कोलकाता। भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाल ने गुरुवार को कोलकाता के एंटाली इलाके में निष्कासित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता संदीपन साहा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने विधायक और उनके पिता टीएमसी नेता स्वर्ण कमल साहा पर भूमि हड़पने और वसूली का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों द्वारा संदीपन साहा और उनके पिता की तस्वीरों वाले दो गधों को साथ लाने से विरोध ने सबका ध्यान खींचा। टिबरेवाल ने कहा कि यह प्रतीकात्मक इशारा दोनों नेताओं द्वारा आम लोगों के शोषण को उजागर करने के लिए था।

प्रियंका टिबरेवाल ने कहा, जनता द्वारा लाए गए ये गधे यह दिखाने के लिए हैं कि तृणमूल में दो गधे थे, संदीपन साहा और स्वर्ण कमल साहा। उन गधों ने जनता का पैसा लूटा है। अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों लूटा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पिता-पुत्र की जोड़ी ने आम नागरिकों की जबरन जमीनें कब्जाईं और वसूली की गतिविधियों में शामिल रहे। इन आरोपों पर संदीप न साहा या टीएमसी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

टिबरेवाल ने तृणमूल कांग्रेस में पार्टी विधायकों के एक वर्ग द्वारा बगावत के बाद चल रही राजनीतिक उथल-पुथल पर भी टिप्पणी की। उन्होंने निष्कासित नेता ऋब्रत बनर्जी के पक्ष में एमएलए के एक नए समूह के उभरने पर कहा, ऐसा होना ही था। जहां एक पार्टी चोरों को लेकर बनती है, वहां ऐसा ही होगा।

उनकी टिप्पणियां टीएमसी के गहरे आंतरिक संकट के बीच आईं, जहां 58 विधायकों का समर्थन करने वाला एक विद्रोही गुट विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मान्यता की मांग कर रहा है। इस समूह ने ऋब्रत

बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और संदीपन साहा को मुख्य सचेतक प्रस्तावित किया है, जो दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत औपचारिक विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 15 जून की पेशी के लिए जारी समन पर टिबरेवाल ने कहा, जिन लोगों ने चोरी की है, उन्हें जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला पर बम विस्फोट मामले के संबंध में हाल ही में हुई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की छापेमारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने वहां ऐसा माहौल फैलाया था। अब जब भाजपा की सरकार बन गई है, तो यह सब नहीं चलेगा।

इस बीच टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी समितियों और अग्रिम संगठनों को भंग कर दिया है, जिसका कारण चुनावी हार के बाद एक व्यापक संगठनात्मक समीक्षा और पुनर्गठन अभ्यास बताया गया है।

पश्चिम बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले से जुड़े व्यक्ति को जांच में सहयोग करना और एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर उसके समक्ष पेश होना जरूरी है। एनआईए की एक टीम ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर के दक्षिण बामुनिया क्षेत्र में टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के आवास पर तलाशी और पूछताछ अभियान चलाया। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुए बम विस्फोट की जांच से जुड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी, ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज

अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने 4 जून को सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने संवैधानिक संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और मानहानिकारक बयान दिए थे। शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में, विभिन्न सार्वजनिक भाषणों, राजनीतिक मंचों और मीडिया से बातचीत के माध्यम से, आरोपी ने कथित तौर पर भारत के संवैधानिक संस्थानों, जिनमें भारतीय चुनाव आयोग और चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात केंद्रीय सशस्त्र बल शामिल हैं, के खिलाफ कई भड़काऊ और उत्तेजक बयान दिए हैं। आरोपी ने सार्वजनिक रूप से इन संवैधानिक संस्थानों की निष्ठा, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिससे कथित तौर पर राज्य तंत्र के खिलाफ जनता में अविश्वास और असंतोष पैदा करने का प्रयास किया गया।

इस बारे में बात करते हुए रिंकी चटर्जी सिंह ने कहा कि मेरी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत है। इस शिकायत को औपचारिक रूप से एफआईआर में बदलने में 23 दिन लगेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

नईदिल्ली। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे

सीरीज से पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। फिलहाल कोहली के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होगी।

कोहली को यह चोट आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान लगी थी, जब उन्होंने आरसीबी को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 156 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी और टीम ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता था। इस अनुभवी बल्लेबाज ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए जिसकी बदौलत आरसीबी ने अहमदाबाद में 5 विकेट से खिताबी जीत हासिल की।

कोहली की अनुपस्थिति में भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर अतिरिक्त दबाव आएगा। युवा खिलाड़ियों और मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। चयनकर्ता और टीम प्रबंधन अब यह तय करने में जुटे होंगे कि उनकी जगह अंतिम एकादश में किसे मौका दिया जाए। अफगानिस्तान के खिलाफ यह सीरीज भारत के लिए आगामी बड़े टूर्नामेंटों की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में कोहली की चोट टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है।

वनडे सीरीज शेड्यूल : पहला वनडे - 13 जून, धर्मशाला, दूसरा वनडे - 17 जून, लखनऊ, तीसरा वनडे - 20 जून, चेन्नई।

वनडे टीम : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सपाट बंद हुआ बाजार! सेंसेक्स स्थिर, निफ्टी 23,417 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सीमित दायरे में कारोबार के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ। निवेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति के फैसले का इंतजार करते नजर आए, जो शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। दिन के अंत में निफ्टी50 मामूली बढ़त के साथ 23,416.55 पर बंद हुआ। इसमें 10.95 अंकों यानी 0.05 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। वहीं, सेंसेक्स 13.84 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 74,360.01 पर बंद हुआ। निफ्टी50 के प्रमुख घटकों में इंफोसिस, बजाज फिनसर्व और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। इन शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.46 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

पैरासिटामोल समेत कई दवाओं पर महंगाई की मार

नईदिल्ली। वैश्विक स्तर पर बढ़ी महंगाई और सप्लाई चेन पर दबाव का असर अब दवा बाजार में भी दिखाई देने लगा है। कच्चे माल, समुद्री परिवहन, पैकेजिंग और आयात लागत में बढ़ोतरी के कारण फार्मा कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। इसका असर बाजार में आने वाले नए स्टॉक पर देखने को मिल रहा है, जहां कई दवाओं की कीमतों में 8% से 17% तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन और अन्य कई दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट तथा पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। दवाओं की पैकेजिंग में उपयोग होने वाले प्लास्टिक, एल्युमीनियम और अन्य सामग्री भी महंगी हो गई है, जिससे कंपनियों का खर्च बढ़ा है।

सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी

नईदिल्ली। भारत सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने और रुपए की गिरती कीमत को संभालने के लिए सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई मीटिंग में आयकर कानून में संशोधन के लिए एक बड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये अध्यादेश देश भर में लागू हो जाएगा।वर्तमान में, 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए बॉन्ड पर निवेशकों को 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। सरकार बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले 20% विदहोल्डिंग टैक्स को भी समाप्त करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो भारतीय सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाना है।

कुकू टेक्नोलॉजीज लाएगी 3500 करोड रु. का आईपीओ

नईदिल्ली। कुकू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए गोपनीय रूप से आवेदन फाइल किया है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2,500 करोड़ रुपये से 3,500 करोड़ रुपये (करीब 36 करोड़ डॉलर) जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फार सेल दोनों शामिल होगा। कंपनी अपने कुकू एफएम और कुकू टीवी ब्रांड के अंतर्गत क्रमश: क्षेत्रीय भाषा (वर्नाक्युलर) ऑडियो और शॉर्ट-वीडियो ऐप ऑपरेट करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान लिस्ट होने पर कंपनी का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपये (करीब 1.8 अरब डॉलर) तक का वैल्यूएशन हासिल करना है। यह फाइलिंग ऐसे समय में हुई है जब भारत में माइक्रोड्रामा फॉर्मेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

ब्याज दरें बढ़ाकर रुपये को संभालना आत्मघाती साबित हो सकता है

जनक राज

तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बाजार में भारी बिकवाली से रुपया दबाव में आ गया है। रुपये की गिरती साख के बीच मीडिया में यह सुझाव आता रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ब्याज दरें बढ़ाकर भारतीय मुद्रा संभालनी चाहिए।

इस सुझाव के पीछे मुख्य तर्क यह है कि ब्याज दरें ऊंची रहने से उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है जिससे सट्टेबाजी कम हो जाती है और विदेशी निवेश लाने में आसानी होती है। ब्याज दर का इस्तेमाल आरबीआई मूल्य स्थिरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए करता है। मशहूर टिनबर्गेन सिद्धांत के मुताबिक एक साधन का इस्तेमाल केवल एक लक्ष्य हासिल करने के लिए जाना चाहिए। विनिमय दर निर्यंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल बाजारों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की विश्वसनीयता को चोट पहुंचा सकता है।

दूसरा बात, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ब्याज दर बढ़ाने से रुपये में गिरावट थम जाएगी। वर्ष 2013 में 'टेपर टैंट्रम' के दौरान (जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने घोषणा की कि वह भविष्य में नरमी के कदमों को वापस लेगा) तब ब्याज दर से बचाव रुपये को स्थिर नहीं कर पाया था।

बाजार में सुधार अन्य उपायों से दिखा, खासकर बैंकों के लिए आरबीआई की रियायती विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) जमा स्वैप विंडो के जरिये जुटाई गई 34 अरब डॉलर रकम से काफी मदद मिली थी।

इस बात के कई ठोस सबूत हैं कि ब्याज दरों के जरिये विनिमय दर नियंत्रित करना शायद ही कभी कारगर होता है। अपवाद के तौर पर गंभीर आर्थिक संकट के दौरान ऐसा

किया जा सकता है मगर तब भी ब्याज दरों में बहुत अधिक वृद्धि की जरूरत होती है। भारत में ऐसे हालात अभी नहीं हैं। रुपये पर दबाव मुख्य रूप से तेल की बढ़ती कीमतों के कारण है जिससे चालू खाता घाटा बढ़ रहा है जबकि विदेशी निवेश (एफपीआई) निकलने से रकम की उपलब्धता कम हो रही है।

खास बात यह है कि विदेशी निवेशकों ने ज्यादातर शेयरों से अपनी रकम निकाली है। चूंकि, ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आम तौर पर शेयरों का मूल्यांकन कम हो जाता है और कंपनियों के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है इसलिए रुपया संभालने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल बिकवाली रोकने के बजाय उसे और बढ़ा सकता है। रुपये पर दबाव तो साफ दिख रहा है। हालांकि, इसे बचाने के लिए नीतिगत रीपो दर का उपयोग करने से मौद्रिक नीति का विनिमय दर प्रबंधन के साथ घालमेल हो जाता है। असली चुनौती ऐसे उपाय लागू करना है जो एफपीआई निकासी पर अंकुश लगाए और पूंजी वापस लाने के लिए माहौल दोबारा बनाए।

एफपीआई 2025 और 2026 में लगातार शुद्ध बिकवाल रहे। एफपीआई ने वर्ष 2025 में लगभग 19 अरब डॉलर और 2026 में अब तक 24 अरब डॉलर की बिकवाली की है। फरवरी को छोड़कर इस साल हर महीने एफपीआई शुद्ध बिकवाल रहे हैं।

इस संदर्भ में यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अमेरिका बॉन्ड पर अब 4.6 फीसदी से अधिक रिटर्न मिल रहा है और रुपये पर भारी दबाव है। इसे देखते हुए विदेशी निवेशकों को भारतीय परिसंप ?त्तियों से बहुत ज़्यादा रिटर्न की जरूरत होती है, ताकि वे डॉलर के हिसाब से उतना ही कमा सकें जितना वे कहीं और कमा सकते हैं। वैश्विक जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम होने पर भारत के प्रति उनका झुकाव कम हो जाता है।

एक प्रमुख कारण भारत में पूंजीगत लाभ कर है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों से अल्पकालिक लाभ पर 20 फीसदी और दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 फीसदी कर का भुगतान करते हैं। दूसरी तरफ सिंगापुर, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्द्धी बाजार विदेशी निवेशकों के पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगाते हैं।

कमजोर रुपया और अमेरिका में ऊंची दरों के कारण रिटर्न पहले से ही दबाव में हैं और उस पर करों में यह अंतर विदेशी निवेशकों को भारत के बजाय दूसरे अधिक कर अनुकूल देशों की तरफ धकेल देता है।

मुख्यमंत्री साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त

महिलाओं के खातों में अंतरित हुए 642.27 करोड़

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है।जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित नियद नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना आज केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की हर महिला सशक्त, स्वावलंबी और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई धारा प्रवाहित हुई है और लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली तथा आर्थिक स्थिरता का नया अध्याय जुड़ा है।

मुख्यमंत्री साय ने भिखमपुरा के पंचमुखी सिद्ध हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम भिखमपुरा पहुंचकर स्वामी शिवानंद विद्यापीठ एवं गौसेवा आश्रम परिसर स्थित पंचमुखी दक्षिणाभिमुख सिद्ध हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और राज्य की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन दिनों सुशासन तिहार के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों का सतत दौरा कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से वे सीधे आमजन से संवाद स्थापित कर शासन की योजनाओं और सेवाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं।भिखमपुरा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गौसेवा आश्रम परिसर में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से उन्हें मिल रहे लाभों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए प्रशासन सीधे लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है।इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय नागरिक, आश्रम से जुड़े सदस्य तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

एनईपी के सपनों को साकार करेगी व्यावहारिक शिक्षा: शिक्षामंत्री वर्मा

रायपुर। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री टंक राम वर्मा ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति (हृश्वक्क) के अद्यतन पाठ्यक्रम पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी पुस्तक मानचित्र निर्माण के सिद्धांत का विमोचन किया। उच्च शिक्षा एवं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली इस बेहद उपयोगी पुस्तक का लेखन प्रदेश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. राजू चंद्राकर और डॉ. लोकेश पटेल द्वारा किया गया।

विमोचन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने दोनों विद्वान लेखकों को उनके इस उत्कृष्ट अकादमिक कार्य के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (हृश्वक्क) का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक विद्यार्थियों को मानचित्र कला जैसी महत्वपूर्ण विधा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं को सरलता से समझने में अत्यंत सहायक और उपयोगी सिद्ध होगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और मातृभाषा व सरल भाषा में ऐसी उच्च स्तरीय अकादमिक पुस्तकों का आना एक सराहनीय कदम है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रख्यात समाजसेवी एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री जागेश्वर यादव ने भी इस उत्कृष्ट अकादमिक कार्य के लिए दोनों लेखकों को अपनी आत्मीय शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लेखकों के भगीरथ प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा, ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयास समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी को एक नई, सकारात्मक और प्रगतिशील दिशा प्रदान करते हैं।

नियमों की सही जानकारी ही व्यापार का सुरक्षा कवच : थौरानी

रायपुर। आज चेम्बर भवन में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं छत्तीसगढ़ सीमेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जीएसटी के ई वे बिल एवं बिल टू शिफ्ट टू से संबंधित नए नियमों को लेकर महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के ई वे बिल एवं बिल टू शिफ्ट टू से संबंधित नए नियमों के प्रति व्यापारियों को जागरूक करना था।इस अवसर पर हाल ही में भारत सरकार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में कनाडा के सफल व्यापारिक प्रवास से लौटे चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी का सीमेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल-श्रीफल से आत्मीय अभिनंदन किया गया। कार्यशाला में सीए टीम के सभी सदस्यों ने ई वे बिल एवं बिल टू शिफ्ट टू से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक और कानूनी पहलुओं पर अपने अलग-अलग विचार साझा किए। चेम्बर वाईस चेयरमेन सी.ए. चेतन तारवानी ने बिलिंग प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए जानकारी दी कि ई-वे बिल के नियमों में आ रहे बदलावों का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में ईमानदार व्यापारी भी फंस जाते है बिल टू-शिप टू के मामलों में यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि पार्ट-ए और पार्ट-बी की प्रविष्टियां बिल्कुल सटीक हों, ताकि रास्ते में गाड़ी पकड़े जाने की नौबत न आए। इनपुट टैक्स क्रेडिट और मिलान पर बात रखते हुए कहा कि नए नियमों के तहत यदि बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस में जरा सी भी तकनीकी गड़बड़ी होती है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक होने का खतरा रहता है। सीमेंट व्यापार में भारी मात्रा में माल का परिवहन होता है, इसलिए दस्तावेज तैयार करते समय पिन कोड और दूरी की ऑटो-कैलकुलेशन की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।

रायपुर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बड़े बकायादारों को थमाया नोटिस

रायपुर। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बड़े बकायादारों को थमाया नोटिस, राजस्व वसूलने कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देशरायपुर। नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल समयसीमा की बैठक लेकर विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर सम्बंधित निगम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को नगर निगम रायपुर के सभी बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर उनसे सम्पूर्ण बकाया राजस्व वसूलने नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने सभी 10 जोनों को मिलाकर प्रतिदिन एक करोड़ रूपये का राजस्व वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है. आयुक्त ने दिनांक 30 जून 2026 तक सम्पतिकर की वर्ष 2026-27 हेतु अदायगी किये जाने पर सम्पति करदाताओं को 6.25 प्रतिशत की सम्पतिकर में छूट का लाभ प्रदान कर अधिकाधिक राजस्व वसूलने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैं. आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों सहित समस्त जोनों के सम्पूर्ण राजस्व अमले को सनहाल की राजस्व वसूली पर निगम हित में लगातार फोकस करने के निर्देश दिए हैं.आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को मानसून की पहली बारिश होने के पूर्व अधिक से अधिक स्थानों में वर्षा जल संचयन हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना सुनिश्चित करने निर्देशित किया है. आयुक्त ने बारिश में जल भराव के स्थलों को चिन्हित कर वहाँ वर्षा जल संचयन हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना प्राथमिकता से सुनिश्चित करने सभी जोन कमिश्नरों को शहर क्षेत्र में भूजल स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से निर्देशित किया है।

आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के सभी प्रकरणों पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

नीट मामले में प्रधान को बर्खास्त किया जाए: बैज

रायपुर। नीट के पेपर लीक मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयुआई कार्यकर्ताओं पर किये गये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए बर्बरता पर उतर आई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्रों के हक की मांग करने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और

प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे। भाजपा सरकार छात्रों के प्रदर्शन से घबरा गई भाजपा ने उनके खिलाफ लाठियों से प्रहार करवाया।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदर्शन के वीडियो से स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण ढंग से नारे लगाते जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बेवजह ही लाठीचार्ज किया है। कुछ कार्यकर्ताओं और मीडियाकर्मियों को तो पुलिस द्वारा घेरकर पीटा गया है, कई लोगों को चोटें आई है। नीट के दोषियों पर कार्रवाई की मांग करना भी भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह लाठीचार्ज करके अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछली बार भी नीट के पेपर लीक मामले में मोदी सरकार ने किसी की जवाबदेही तय नहीं की।

शहरों और गांवों की जनता ने भाजपा को नकार दिया: शुक्ला

रायपुर। नगर निगमों तथा नगर पंचायतों एवं पंचायतों के उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के शहरों और गांवों की जनता ने भाजपा को नकार दिया। पंचायतों के उपचुनाव के विभिन्न पदों पंचों, जनपदों में कांग्रेस के 543 समर्थित प्रतिनिधि चुनाव जीते है। जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर निगम के वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते

है। अंतागढ़ के वार्ड में कांग्रेस चुनाव जीती है। नगर पंचायतों में घुमका और पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते है। नगर पंचायतों 30 वार्डो में भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद भले भाजपा जीती लेकिन 8 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आये। कांग्रेस वहां भी चुनाव जीतकर आई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तमाम सरकारी मशीनरी लगाने के बाद तथा सत्ता बल धन बल का उपयोग करने विपक्षी प्रत्याशियों को डराने धमकाने के बाद आये। यह चुनाव परिणाम बताते है राज्य में अब भाजपा का अवसान शुरू हो गया है। जनता ने भाजपा के कुशासन को नकार दिया है।

ट्रिपल इंजन सरकार में सफाई व्यवस्था ठप्प: शुक्ला

रायपुर। ट्रिपल इंजन सरकार की कमीशनखोरी के चलते शहर में गंदगी फैलने का आरोप लगाते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार की कमीशनखोरी ने रायपुर को कचरापुर बना दिया। सफाई कार्य में लगे ठेकेदारों को बीते कई महीने से भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान मांगने पर ट्रिपल इंजन सरकार में 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप ठेकेदारों ने लगाया है। अभी कुछ दिन पहले रामकी

कम्पनी के खिलाफ कचरा ढोने वाले वाहन चालक एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना, वेतन में बढ़ोत्तरी करने सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन किये थे। उस दौरान भाजपा सरकार ने आंदोलन को कुचलने दमनकारी कार्यवाही किया था। आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब ठेकेदार आंदोलन पर है। ये ट्रिपल इंजन सरकार की कमीशनखोरी का नतीजा है।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में निकाय में सब कुछ ठीक होने का दावा हवा हवाई निकला। सफाई व्यवस्था भी ठीक से करवा नहीं पा रहे है। ठेकेदारों को भुगतान नहीं दिया जा रहा है। निगम द्वारा अलग से जो वार्डो के लिए सफाई टीम बनाई गई।

प्रदेश में नेम चेंजर सरकार चल रही: वंदना राजपूत

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार में क्षमता नहीं है कि वह कोई नई योजना कम कर सके। वह कांग्रेस सरकार के समय चलाई जा रही योजनाओं के नाम बदल कर झूठी वाहवाही लेने पर लगी है। जिनमें अपनी लाईन बड़ी करने की क्षमता नहीं होती, वे दूसरो की लाईन मिटाते है। भाजपा सरकार वही कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने

कहा कि मेधावी अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये जवाहर उत्कर्ष योजना चलाई जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति उत्कर्ष योजना कर दिया गया। यह भाजपा सरकार की गलत परंपरा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार नेम चेंजर सरकार है। भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में चल रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना-कृषक उन्नति योजना कर दिया। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना-शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना कर दिया। इंदिरा गांधी शुद्ध पेयजल योजना-पं. दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना कर दिया। इंदिरा गांधी एलईडी पथ प्रकाश योजना-पं. दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना कर दिया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर बनेगी मानव श्रृंखला

रायपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फ्यूचर ऑफ इंडिया (भारत का भविष्य) अभियान के तहत शुक्रवार 5 जून को सुबह 7:30 बजे से 8.30 बजे तक तेलीबांधा तालाब स्थित मरीन ड्राइव, रायपुर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा एवं विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।मानव श्रृंखला के माध्यम से जंगलों की रक्षा, जल संरक्षण, स्वच्छ वायु और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संदेश दिया जाएगा। साथ ही लोगों को जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में विज्ञान कार्यकर्ता, शिक्षक, डॉक्टर, प्रोफेसर, किसान, मजदूर, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की रायपुर इकाई की सचिव एवं शिक्षाविद् डॉ. अंजू मेश्राम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों को बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय चुनौतियों से बचाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान वृक्षों के संरक्षण, जल बचाने और हरियाली बढ़ाने के संदेश पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

सर्वाधिक वेंडर पंजीयन श्रेणी में मिली उपलब्धि, नई दिल्ली में होगा सम्मान

छत्तीसगढ़ पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार में द्वितीय स्थान

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर = मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का चयन माह का सौर अभियान -सर्वाधिक वेंडर पंजीयन श्रेणी में द्वितीय स्थान के लिए किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है।

यह उपलब्धि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य के सतत प्रयासों तथा जनभागीदारी का परिणाम है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में उन्हें 4 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के दो वर्ष एक करोड़ सौर छतों की ओर बढ़ता भारत में शामिल होने तथा राज्य की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

प्रमुख सचिव (ऊर्जा) तथा पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि के लिये अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। यह सम्मान राज्य में सौर ऊर्जा अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक वेंडर पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस श्रेणी में एक महीने में छत्तीसगढ़ ने 86 वेंडर पंजीयन दर्ज कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस तरह छत्तीसगढ़ में 1222 वेंडर पंजीकृत हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ ने महिला स्वसहायता समूहों को भी वेंडर बनाया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिजली बिल में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 1 जून 2026 की स्थिति में राज्य में 1 लाख 93 हजार 371 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 61 हजार 700 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा 1 लाख 32 हजार 28 स्थापना कार्य प्रगति पर हैं। 16 हजार उपभोक्ताओं के शून्य बिजली बिल का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत 45 हजार 978 हितग्राहियों को केंद्र शासन से 353.20 करोड़ रुपये तथा 40 हजार 910 हितग्राहियों को राज्य शासन से 122.62 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं।

जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन की पहचान: मंत्री नेताम

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप संचालित सुशासन तिहार के तहत आज रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत खरसिया के ग्राम छोटे मुड़पार में विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं।

कार्यक्रम में प्रदेश के आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन एवं पशुधन विकास मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में ग्रामीणों से 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अनेक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों के समय-सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सुशासन तिहार इसी संकल्प का परिणाम है, जहां शासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और उनका समाधान कर रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रशासन की स्थापना की जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.